सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 03, नई दिल्ली | रविवार, 19 मार्च 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

बुरा वक्त भी हमे कुछ नया सीखा जाता है, कुछ नया नहीं तो, हमे अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है।

इनसाइड

रविवार रात से न बुक होगी और न ही रद्द होंगे टिकट, साढ़े तीन घंटे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम रहेगा बंद

नई दिल्ली। तकनीकी सुधार के लिए रेलवे ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। रविवार रात 11:45 बजे से सुबह 3:15 बजे तक पीआरएस पूछताछ को बंद रखा जाएगा। इस दौरान रेलवे संबंधी सभी तरह की कंप्यूटरीकृत पूछताछ सेवा बंद रहेगी। रविवार मध्यरात्रि से सुबह तक करीब तीन घंटा 30 मिनट तक रेलवे से संबंधित जानकारी में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आईवीआरएस/टच स्क्रीन, कॉल सेंटर (टेलीफोन नंबर-139) के माध्यम से भी किसी तरह की ट्रेनों से संबंधित जानकारी नहीं मिलेगी। साथ ही कंप्यूटर द्वारा चालू आरक्षण बुकिंग का कामकाज भी बंद रहेगा। न तो यात्रा टिकट जारी होंगे और न ही निरस्त कराया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार, 139 पूछताछ सेवा के साथ ही इस दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी नहीं होगी। रेलवे स्टेशन स्थित ना तो डोरमेट्री की ऑनलाइन बुकिंग होगी और ना ही रिटायरिंग रूम की। गतिशील डेटाबेस को बेहतर करने के लिए अस्थायी रूप से सेवा बाधित रहेगी।

दिल्ली-6 के सदर बाजार में ट्रेंच कटर मशीन करेगी खुदाई

डबल-डेकर भूमिगत मैट्रो स्टेशन का निर्माण

> उम्मीद है कि एक माह में स्टेशन का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा।

एस.टी. सेठी

नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली -6 में मैट्रो का निर्माण कार्य शुरू से ही चैलेंजिंग भरा रहा है। इसी कडी में फेज-4, में एक बार फिर मैट्रो पुरानी दिल्ली से होकर गुजरेगी। वैसे भी यहां स्टेशन के लिए बेहद कम जगह है। वहीं दूसरी और सदर बाजार की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर इसके नीचे गहराई में अरावली पर्वत माला पहाड है। इस खुदाई और पहाड कटाई के लिए (डीएमआरसी) यहां चैन्नई के बाद पहली बार ₹ टेंच कटर मशीन ₹से खुदाई करने जा रही है। इस टेंच कटर मशीन से पहाड कटाई की नई तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल करना जरूरी ही नहीं बल्कि जरुरत भी है। सदर बाजार में भूमिगत डबल-डेकर मैट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य को अंजाम देने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है।

राजधानी दिल्ली में फेज- 4, में दो जगहों पर डबल-डेकर कॉरिडोर पर वाहनों के लिए फ्लाई ओवर और उसके ऊपर मैट्रो कॉरिडोर होगा। इसी क्रम में फेज-4, में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम, -आरके आश्रम कॉरिडोर के साथ ही सदर बाजार में डबल-डेकर भूमिगत मैट्रो स्टेशन बनाने पर भी दिल्ली मैट्रो रेल निगम। (डीएमआरसी) विचार कर रहा है। इसका कारण यह है कि सदर बाजार में जमीन की कमी आढे आ रही है। इसलिए सदर बाजार में डबल डेकर भूमिगत स्टेशन बनेगा।

उम्मीद है कि एक माह में स्टेशन का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। वहीं (जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर वर्तमान मजेंटा लाइन(जनकपुरी पश्चिम-बोटेनिकल गार्डन) की विस्तार परियोजना है। इस नए कॉरिडोर की लंबाई 28.92 किलोमीटर होगी। इसका 19.42 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटिड व 9.40 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत होगा। इस कॉरिडोर पर कुल 22 मैट्रो स्टेशन होंगें। जिसमें से 15 स्टेशन एलिवेटिड व 7 भूमिगत होगें। इस मैट्रो लाइन पर एलिवेटिड का सबसे बडा भूमिगत कॉरिडोर डेरावाल नगर से आरके आश्रम के बीच होगा। जिसकी लंबाई 7.46 किलोमीटर होगी। इसका कार्य प्रगति पर है। डेरावाल नगर, घंटाघर, पुल बंगश,सदर बाजार, नबी क्रीम व आरके आश्रम पर स्टेशन होंगें। ये बहुत बडी चुनौती हो सकती है।

डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक सदर बाजार मैट्रो स्टेशन जिस जगह बनाया जा रहा है वहां की मिट्टी में मुख्य रूप से कठोर चट्टाने शामिल है। जिन्हें साधारण मशीनों से काटना आसान नहीं है। इसी वजह से मैट्रो स्टेशन की नींव डायफॉम वॉल के निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ट्रेंच कटर लगाया गया है।ट्रेंच कटर मशीन का इस्तेमाल पहली बार सदर बाजार में हो रहा है। इसकी खासियत है कि नुकीले तेज धारदार दांतो वाली मशीन के दो पाटों में एक दूसरे के अपोजिट घूमते हुए कटाई करते हैं। कम्प्यूटर से चालित यह कटर मशीन जमीन के अंदर प्रवेश करती चली जाती है। वह मिट्टी, चट्टान और बेटोंनाइट को मिक्सर में खींचकर बॉक्स की ओपनिंग की ओर ले जाता है। जानकारी के मुताबिक अब तक सिर्फ चैन्नै- मैट्रो रेल कार्पोरेशन लि. ने ही इसका इस्तेमाल किया है। ये ही ट्रेंच मशीन अब सदर बाजार मैट्रो स्टेशन में प्रयोग की जा रही है।

शहरों की तरह हमें स्मार्ट गांवों की भी जरूरत, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनें किसान : गडकरी

मुंबई। केंद्रीय मंत्री ने कहा दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की विरासत को आगे बढ़ाते हुए किसानों के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना होगा। किसानों को भोजन के आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ ऊर्जा का आपूर्तिकर्ता बनना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि स्मार्ट शहरों के साथ-साथ भारत को स्मार्ट गांवों की भी जरूरत है। वह नासिक जिले के सिन्नार तालुका के नंदूर शिंगोटे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की प्रतिमा और स्मारक का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। गडकरी ने कहा, मुंडे ने किसानों के साथ न्याय करने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व किया। स्मार्ट गांव अवधारणा को लागू करने की आवश्यकता : नितिन गडकरी गडकरी ने कहा, उन्होंने (गोपीनाथ मुंडे) कृष्णा घाटी, तापी और विदर्भ सिंचाई परियोजनाओं जैसी योजनाओं के जरिए किसानों के लिए काम किया।

100 की रफ्तार से किरावली-इटावा नेशनल हाईवे पर दौड़ेंगे वाहन

आगरा। किरावली-इटावा नेशनल हाईवे से कागारौल, सैंया, इरादतनगर, शमशाबाद फतेहाबाद और बाह जाने वालों को बड़ा फायदा होगा। आगरा जिले की सड़कों की सूरत जल्द बदलने वाली है। फतेहपुर सीकरी के सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आगरा के लिए 500 करोड़ रुपये की सड़कें और पुल स्वीकृत कराए हैं। इनमें किरावली से सैंया, फतेहाबाद, बाह होकर इटावा तक नया नेशनल हाईवे नंबर 321, पृथ्वीनाथ फाटक से महुअर किरावली तक 17 किमी आगरा-जयपुर मार्ग को फोरलेन करने और पृथ्वनीथ फाटक पर ओवरब्रिज को मंजूरी दी गई है। सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उनके प्रस्तावों को स्वीकृत किया है। फतेहपुर सीकरी के लिए नया हाईवे लाइफ लाइन साबित होगा। पूरे संसदीय क्षेत्र को एक सड़क से जोड़ा गया है। किरावली से कागारौल, सैंया, इरादतनगर, शमशाबाद फतेहाबाद होकर बाह, उदीमोड़ व इटावा तक नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 321 का नाम दिया गया है। इसे एनएचएआई बनाएगा। पहले चरण में किरावली से कागारौल 15 किमी लंबी और 10 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी जिसमें 150 करोड़ की लागत आयेगी।

हिमाचल में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण होगा

परिवहन विशेष संवाददाता

शिमला। हिमाचल में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण करेंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद इंदु बाला गोस्वामी को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि हिमाचल में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण करेंगे। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कुल 7,662.47 करोड़ की लागत से 781 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए विश्व बैंक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण सहायता प्रदान करेगा।

मंत्री ने कहा कि इस ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य मौसम में बदलाव, जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण करना है। इसमें सीमेंट से ट्रीट किए गए सब बेस, स्थानीय उत्पादों जैसे फ्लाई ऐश, प्लास्टिक के उपयोग, कोको जूट फाइबर आदि किफायती घरेलू, स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके ग्रीन प्रौद्योगिकी को मुख्य धारा में समाहित किया जाएगा।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़े : जितेंद्र बंसल

परिवहन विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। आज आदर्श नगर मंडल किसान मोर्चा एवं भावी पार्षद उम्मीदवार जितेंद्र बंसल एवं युवा समाजसेवी तरुण शर्मा की टीम ने मिलकर सरदार देवेंदर सिंह को जिला टास्क फोर्स फरीदाबाद, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सदस्य के हरियाणा सरकार में सदस्य बनाने पर बधाई एवं जोर-शोर से बुके एवं फूल मालाओं से स्वागत किया। तरुण शर्मा ने कहा कि आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़े हमारी पूरी टीम हम सभी आपके साथ साथ हैं बस आप हमें समय-समय पर मार्गदर्शन करते रहें इस स्पेशल स्वच्छ भारत मिशन फरीदाबाद के अभियान में आपको पूरा पूरा सहयोग दिन रात मिलकर करेंगे जैसा कि आप सबको पता है कि सरदार देवेंद्र सिंह पिछले लगभग 13 वर्षों से सड़क सुरक्षा के,स्वच्छ भारत ,ब्लड डोनेशन ,MCF ,स्मार्ट सिटी सदस्य ,लीगल अवेरनेस प्रति एवं सामाजिक कार्यों के लिए लोगों को स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार,मेंबर ऑफ़ पार्लिमेंट ,रेड क्रॉस का सदस्य ,जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी एवं जिला सड़क सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के नाते दिन रात जागरूक कर रहे है।

हमारा मिशन ही श्री गुरु नानक देव जी की सेवा है साध संगत की सेवा करना है आप सभी के स्नेह, प्यार एवं आशीर्वाद से आज मुझे सरदार देवेंद्र सिंह को स्टेट टास्क फोर्स,स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन श्री सुभाष चन्द्रा जी एवं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जिला टास्क फोर्स फरीदाबाद, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सदस्य के रूप में चुना गया है मैं देवेंद्र सिंह स्टेट टास्क फोर्स, स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन श्री सुभाष चन्द्रा जी एवं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद श्री विक्रम सिंह जी, नगर निगम फरीदाबाद कमिश्नर श्री जितेंद्र कुमार दहिया का एवं रोड सेफ्टी ओमनी फॉउण्डेशन,चरड़ी कला रहे खालसा हरियाणा की पूरी टीम का एवं फरीदाबाद की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होने सरदार देवेंदर सिंह एवं हमारी संस्था की पूरी टीम की मेहनत पर भरोसा दिखाते हुए मुझे ये अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हरियाणा सरकार के द्वारा दी है और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सरदार देवेंद्र सिंह इस जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से पूरा करूंगा। हम सभी के सहयोग लेकर ही आगे बढ़ेंगे।

आज इस सम्मान समारोह में आदर्श नगर मंडल किसान मोर्चा एवं भावी पार्षद उम्मीदवार जितेंद्र बंसल,युवा समाजसेवी तरुण शर्मा,मनोज एडवोकेट,नवीन सिंगला एवं रोड सेफ्टी ओमनी फॉउण्डेशन के सीनियर वाईस प्रेजिडेंट सरदार नरेंदर सिंह ,जसबीर सिंह मौके पर उपस्थित थे।

लग्जरी बस से चारधाम की यात्रा केवल 5700 रुपये में

देहरादून। तीन श्रेणियों की बसें श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन कराएंगी। एक यात्री के लिए लग्जरी बस का किराया 5700 रुपये है। 10 दिनों की यात्रा सरकार की निगरानी में रोटेशन समिति कराएगी। इस साल 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के सड़क मार्ग का किराया तय हो गया है। तीन श्रेणियों की बसें श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन कराएंगी। एक यात्री के लिए लग्जरी बस का किराया 5700 रुपये है। 10 दिनों की यात्रा सरकार की निगरानी में रोटेशन समिति कराएगी। बस सेवा की बुकिंग ऋषिकेश में ऑफलाइन होगी।

यात्रा रुट: ऋषिकेश-बड़कोट (पहला दिन-विश्राम)-यमुनोत्री धाम (दूसरा दिन)-बड़कोट (विश्राम)-उत्तरकाशी (तीसरा दिन-विश्राम), गंगोत्री धाम (चौथा दिन)-उत्तरकाशी (विश्राम)- सोनप्रयाग या गुप्तकाशी (पांचवां दिन-विश्राम)-केदारनाथ धाम (छठवां दिन-विश्राम)- सोनप्रयाग या गुप्तकाशी (सातवां दिन-विश्राम)-पीपलकोटी (आठवां दिन-विश्राम)-बदरीनाथ धाम (नौंवा दिन)-पीपलकोटी (विश्राम)-ऋषिकेश (10 वां दिन)।

आतिशी ने मंत्रालय संभालते एक्शन मोड में आते हुए दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों पर नजर रखना शुरू कर दिया

चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने पहुंची आतिशी, जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश

दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी शनिवार को चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने पहुंची हैं। इस दौरान उनके साथ विभाग और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने फ्लाईओवर के कार्य को 50 की जगह 30 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आतिशी ने मंत्रालय संभालते एक्शन मोड में आते हुए दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। अब शनिवार को आतिशी चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पर जारी मेंटेनेंस कार्य का निरीक्षण करने पहुंची हैं।

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों संग किया निरीक्षण

आतिशी ने चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के निरीक्षण की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें साझा कर दी है। इन तस्वीरों में आतिशी पुलिस ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रही हैं और मेंटेनेंस कार्य पर चर्चा कर रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आम लोगों को ट्रैफिक जाम से जल्द निजात मिले इसके लिए PWD चिराग फ्लाईओवर पर दिन-रात युद्धस्तर पर काम कर रही है।

आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी दिल्ली समय-समय पर जरुरत के अनुसार, फ्लाईओवरों की मरम्मत का कार्य करती है। इसी दिशा में वर्तमान में चिराग दिल्ली फ्लाईओवर की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाईओवर के एक हिस्से को बंद किया गया है। इस कारण उस पर ट्रैफिक बढ़ गया है।

जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश

पीडब्ल्यूडी के अनुसार मरम्मत का कार्य पूरा करने में 50 दिन का समय लगेगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरम्मत के काम को दोगुनी रफ़्तार से करते हुए उसे महीने भर के भीतर पूरा किया जाए।

इनसाइड

सर्वाइकल कैंसर का खतरा युवा महिलाओं को ज्यादा, अपोलो की डॉक्टर सारिका गुप्ता ने बताए बचाव के तरीके

कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि की वजह से हो जाता है. कैंसर कई तरह के होते हैं. इनमें से एक सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) होता है, जो महिलाओं में होने वाला कॉमन कैंसर है. दुनियाभर में हर साल बड़ी तादाद में महिलाएं महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं. चिंताजनक बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम उम्र की महिलाओं को ज्यादा होता है. आज कैंसर स्पेशलिस्ट से जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है.

नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी ओन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सारिका गुप्ता के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर महिलाओं की बच्चेदानी के मुख में होने वाला कैंसर है. इसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है. आमतौर पर 35 साल से लेकर 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. यह कैंसर दो तरह का होता है- पहला लो ग्रेड और दूसरा हाई ग्रेड. लो ग्रेड कैंसर धीरे-धीरे फैलता है, जबकि हाई ग्रेड कैंसर तेजी से फैलता है और इसमें मौत का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे में सही वक्त पर इलाज कराना बेहद जरूरी है.

ऐसी महिलाओं को खतरा ज्यादा

डॉक्टर सारिका गुप्ता कहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर का खतरा उन महिलाओं को ज्यादा होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो और एचआईवी या अन्य कोई गंभीर बीमारी हो. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जेनिटल हाइजीन की कमी और जल्दी बच्चे होने वाली महिलाओं को इसका जोखिम ज्यादा होता है. इसके अलावा स्मोकिंग करने से भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं को इससे बचने के लिए समय-समय पर स्क्रीनिंग करानी चाहिए. सर्वाइकल कैंसर का पता प्री-कैंसरस स्टेज में भी लगाया जा सकता है और सही इलाज के जरिए कैंसर से बचा भी जा सकता है.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण

– पार्टनर के साथ संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग
– पीरियड्स के बीच अनियमित माहवारी होना
– बदबूदार पानी आना या ब्लड स्ट्रीम डिस्चार्ज
– मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना

सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट और बचाव

डॉक्टर के अनुसार सर्वाइकल कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में हो, तो सर्जरी के जरिए इसका इलाज किया जाता है. एडवांस स्टेज में कीमोथेरेपी की जरूरत होती है. हर मरीज की कंडीशन को देखकर ही ट्रीटमेंट किया जाता है. जितना जल्दी इसका पता लग जाए, मौत का खतरा उतना कम हो सकता है. बचाव की बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए HPV का टीका लगवाएं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें. स्मोकिंग से दूरी बनाएं और संबंध बनाते वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें. समय-समय पर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी जांच करवाएं.

5 सेफ्टी टूल्स महिलाएं हैंड बैग में जरूर रखें साथ, मुसीबत में आएंगे बहुत काम कैरी करने में भी नहीं होगी दिक्कत

अकेले ट्रैवल करते समय ज्यादातर महिलाएं अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित रहती हैं. खासकर शाम या रात के वक्त महिलाओं का अकेले सफर करना सुरक्षित नहीं होता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो हैंड बैग में अपने साथ कुछ सेफ्टी टूल्स (Safety tools) रख सकती हैं. जो कि ना सिर्फ मुसीबत में आपके काम आएंगे बल्कि इन्हें कैरी करने में भी आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी. घर से निकलते समय ज्यादातर महिलाएं हैंड बैग में मेकअप प्रोडक्ट्स जैसी जरूरत की सारी चीजें रखती हैं. मगर ऐसे में कई महिलाएं अक्सर अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देती हैं. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कुछ वुमन सेफ्टी टिप्स, जिसे फॉलो करके आप अकेले भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चत कर सकती हैं.

पेपर स्प्रे रखें: महिलाओं के लिए हैंड बैग में पेपर स्प्रे रखना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. पेपर स्प्रे की छोटी सी बोतल आपको बड़ी परेशानी से दूर रखने में सहायक हो सकती है. वहीं मार्किट में भी पेपर स्प्रे की अलग-अलग साइज की बोतलें आसानी से मिल जाती है.

कैंची रखें: ऑफिस पर्पस या रोजमर्रा के अन्य कामों में कैंची का इस्तेमाल काफी कॉमन होता है. ऐसे में आप अपने साथ हैंड बैग में कैंची भी रख सकती हैं. इससे ना सिर्फ आप कई कामों को आसान बना सकती हैं बल्कि अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकती हैं.

सेफ्टी पिन यूज करें: सेफ्टी पिन का इस्तेमाल महिलाओं के डेली रूटीन में आम होता है. आमतौर पर ड्रेस को टक करने के लिए महिलाएं सेफ्टी पिन की मदद लेती हैं. मगर सेफ्टी पिन आपके लिए बेस्ट सेफ्टी टूल भी साबित हो सकती है. इसे हमलावर पर चुभाकर आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं.

नेलकटर या स्विस नाइफ कैरी करें: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिलाएं अपने बैग में नेलकटर या चाकू कैरी कर सकती हैं. खासकर स्विस नाइफ रखना आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. जिसकी मदद से आप हमलावार पर तुरंत पलटवार कर सकती हैं.

चाबी की मदद लें: अकेले सफर करने के दौरान चाबी का इस्तेमाल करके आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं. हमलावर के अटैक करते ही आप चाबी के नुकीले हिस्से की मदद से तुरंत रिएक्ट कर सकती हैं. इसलिए घर से निकलते समय किसी बड़ी नुकीली चाबी को हैंड बैग में जरूर रख लें.

व्हट्सअप चैट करने में महिलाएं पुरुषों से आगे, सर्वे में खुलासा, मेंटल हेल्थ से जुड़ा है मामला

व्हाट्सएप पर चैट करने में महिलाएं पुरुषों से काफी आगे हैं. हाल ही में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन (Mental Health Helpline) की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि टेलिफोन पर कंसल्टेशन या काउंसलिंग लेने के बजाय महिलाएं व्हाट्सएप चैट (WhatsApp Chat) के माध्यम से गोपनीय तरीके से मदद लेना पसंद करती हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स फेसबुक (Facebook), ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, व्हाट्सएप (WhatsApp) या अन्य किसी भी एप्लिकेशन का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. चाहे किसी समस्या का समाधान ढूंढना हो, मनोरंजन करना हो, जानकारी लेनी-देनी हो या सगे-संबंधियों से बातचीत करनी हो तो लोग इन एप्स (App) का इस्तेमाल करते हैं. कभी-कभी चैट में मैसेज टाइप करते-करते उलझन सी भी महसूस की होगी लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं है. व्हाट्सएप पर चैट करना (WhatsApp Chatting) महिलाओं को न केवल फोन पर बात करने के मुकाबले ज्यादा आसान लगता है बल्कि कॉनफिडेंशियल भी लगता है. वे व्हाट्सएप चैट करने में पुरुषों से काफी आगे हैं. खास बात है कि ये चैट भी इस हेल्पलाइन 9999666555 नंबर पर की गई है जो एक मेंटल हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का है.

मानसिक स्वास्थ्य संगठन वंद्रेवाला फाउंडेशन की फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन के 3 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर मेंटल इश्यूज को लेकर सलाह और परामर्श लेने वालों में युवा आबादी ने सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का उपयोग किया है. जबकि मध्यम आयु वर्ग और उससे ऊपर के लोगों ने टेलीफोनिक बातचीत को अधिक पसंद किया.

आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश युवा अपने मानसिक स्वास्थ्य की मदद के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं और इसे बेहतर मानते हैं. 18 वर्ष से कम आयु के 65 फीसदी, 18-35 आयु वर्ग के 50 फीसदी, 35-60 आयु वर्ग के 28.3% और 60 वर्ष से अधिक आयु के 8 फीसदी लोगों ने मेंटल हेल्थ के लिए व्हाट्सएप यूज किया है.

53 फीसदी महिलाएं जबकि पुरुष 42 फीसदी..

फाउंडेशन के डेटा के अनुसार लगभग 53 फीसदी महिलाएं व्हाट्सएप चैट का उपयोग करके हेल्पलाइन से संपर्क करना पसंद करती हैं, जबकि 42 फीसदी पुरुष व्हाट्सएप चैट का उपयोग करना पसंद करते हैं. वहीं बाकी मामलों में लोग टेलिफोन के द्वारा काउंसलिंग लेते हैं.

खास बात है कि व्हाट्सएप ने उस वर्ग को सबसे ज्यादा राहत दी है जो शायद कभी भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता ऑफलाइन क्लीनिकों पर जाकर नहीं ले सकता था. खासतौर पर ऐसी महिलाएं, लड़कियां और युवक जो अपने परिवार या साथियों को बिना बताए अपने मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं वे व्हाट्सएप का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. वे इसे गोपनीय मानते हैं और समय की उपलब्धता के अनुसार साइलेंट तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान हासिल कर पाते हैं.

सुसाइड के विचारों से जूझ रहे लोग

फाउंडेशन की प्रमुख और परोपकारी, प्रिया हीरानंदानी वंद्रेवाला कहती हैं, 'हमसे संपर्क करने वाले एक तिहाई लोगों ने हमें बताया कि वे मानसिक बीमारी, चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं. 2022 में भारत में हत्याओं और कोरोना वायरस से ज्यादा जानें आत्महत्या ने लीं. भले ही आज देश का हर मेडिकल छात्र मनोचिकित्सक बन गया हो, हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य संकट को हल करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं. इसके साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए मदद लेने वाले लोगों के मन में झिझक और डर को दूर करने की भी जरूरत है.

30 की उम्र में हर महिला जरूर कराएं ये 10 टेस्ट, कई घातक बीमारियों से रहेंगी महफूज, डॉक्टर ने बताई असली वजह

अगर आप 30 साल की हो गई हैं तो समय आ गया है कि आप अपने कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को गंभीरता से लें.अगर आप 30 साल की हो गई हैं तो समय आ गया है कि आप अपने कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को गंभीरता से लें.

30 की उम्र के बाद महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं. उनके हॉर्मोन्स में असंतुलन होने लगता है. ऐसे में उम्र बढ़ने के साथ शरीर की सेहत को बनाए रखना और इन बदलावों के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है. यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो डॉ. सारिका गुप्ता के बताए इन महत्वपूर्ण टेस्ट को ज़रूर करा लें.

महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ उनके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं. ये बदलाव उनके लुक, हड्डियों, हॉर्मोन्स और समग्र स्वास्थ्य में हो सकते हैं. 30 की उम्र के बाद महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं. उनके हॉर्मोन्स में असंतुलन होने लगता है. मांसपेशियों की क्षमता कम होने लगती है और यहां तक की प्रजनन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं. ऐसे में उम्र बढ़ने के साथ शरीर की सेहत को बनाए रखना और इन बदलावों के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है. यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो आप इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल (नई दिल्ली) की ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक गायनोकोलॉजी की सीनियर कंसलटेंट डॉ. सारिका गुप्ता के बताए इन महत्वपूर्ण टेस्ट को ज़रूर करा लें, ताकि आप लंबी उम्र तक स्वस्थ और फिट रह सकें.

थायराइड फंक्शन टेस्टः थायरॉक्सिन (टी4) और ट्राईआयोडोथॉयरोनिन (टी3), ये थायराइड ग्लैंड से उत्पन्न होने वाले दो प्रमुख हॉर्मोन हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज़्म पर नियंत्रण बनाए रखते हैं. अगर ये हॉर्मोन सामान्य से अधिक या कम मात्रा में बनने लगें तो इसे क्रमशः हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. महिलाओं में थायराइड से जुड़ी समस्याओं की संभावना पुरुषों की तुलना में अधिक होती है. आप थायराइड फंक्शन टेस्ट के द्वारा पता लगा सकती हैं कि आपके शरीर में थायराइड हॉर्मोंस का स्तर सामान्य है या नहीं.

पैप स्मियर टेस्ट और पेल्विक जांचः पैप स्मियर टेस्ट में सर्विक्स की सेल्स की जांच कर यह पता लगाया जाता है कि महिला में सर्वाइकल कैंसर की संभावना तो नहीं. इस जांच के द्वारा सर्वाइकल कैंसर का निदान बहुत जल्दी हो जाता है. इससे समय पर इलाज किया जा सकता है. इसके अलावा, पेल्विक जांच में महिला के प्रजनन अंगों जैसे वल्वा, गर्भाश्य, वेजाइना, ओवरीज आदि की जांच की जाती है. सभी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि 21 साल की उम्र के बाद उन्हें हर दो या तीन साल बाद नियमित रूप से पेल्विक जांच एवं पैप स्मियर टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए.

मैमोग्राम टेस्टः मैमोग्राम में डॉक्टर स्तनों की स्क्रीनिंग कर स्तन कैंसर का पता लगाते हैं. 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में स्तन कैंसर की संभावना अधिक होती है. हालांकि, समय पर निदान के द्वारा महिला की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है. कैंसर के फैलने से पहले ही अगर इलाज हो जाए तो मरीज के जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है. इसके लिए मैमोग्राम बहुत उपयोगी है, जो कैंसर के जल्द निदान में मदद करता है.

ब्लड प्रेशर और कॉलेस्ट्रॉल की जांचः अगर आप 30 साल की हो गई हैं तो समय आ गया है कि आप अपने कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को गंभीरता से लें. 20 साल की उम्र के बाद हर व्यस्क को हर दो साल में ब्लड प्रेशर और कॉलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए. चाहे आप अपने आप को कितना ही स्वस्थ महसूस करती हों, आपको अपना कॉलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करवाना चाहिए. वजन अधिक है या डायबिटीज है, तो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना अधिक होती है.

कैल्शियम और विटामिन डी टेस्टः ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियों को कमज़ोर होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बोन डेंसिटी ठीक बनाए रखें. ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है, जो दुनिया भर में बड़ी संख्या में महिलाओं में पाई जाती है. हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने विटामिन डी और कैल्शियम के स्तर पर निगरानी रखें. नियमित जांच के द्वारा आप तय कर सकती हैं कि क्या आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं. ब्लड शुगर लेवल की जांच भी है जरूरीः उपरोक्त हेल्थ चेकअप के अलावा, महिलाओं को अपने ब्लड शुगर, त्वचा में होने वाले बदलावों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 30 की उम्र के बाद नए मस्से, तिल होना आम बात है. साथ ही हर 6 महीने में अपना फुल-बॉडी चेकअप कराना न भूलें.

दिल्ली में डिवाइडर से टकराकर कार पलटने से युवक की मौत, एक घायल; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

राजधानी दिल्ली में डिवाइडर से टक्कर के बाद कार के पलटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवका दोस्त घायल हो गया। पुलिस ने इस घटना के बारे में शनिवार को बताया। यह हादसा उत्तर पश्चिम दिल्ली के मंगोलपुरी में हुआ था।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में डिवाइडर से टक्कर के बाद कार के पलटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं, युवका दोस्त घायल हो गया। पुलिस ने इस घटना के बारे में शनिवार को बताया। यह हादसा उत्तर पश्चिम दिल्ली के मंगोलपुरी में हुआ था। उन्होंने बताया कि राज पार्क थाने के अधिकारियों को मंगोलपुरी के एस-ब्लॉक चौक के पास शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि में हादसे की सूचना मिली। पुलिस उपायुक्त (बाहरी) हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जब एक टीम मौके पर पहुंची, तो उन्हें मारुति सुजुकी बलेनो पलटी हुई मिली। घायलों को कार से निकालकर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। जांच में पता चला कि सुल्तानपुरी निवासी अभिषेक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि उसका दोस्त ऋतिक (25) घायल हुआ था। राजपार्क थाने स्टेशन में पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, इसके साथ ही शनिवार को कार जब्त कर ली। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ऋतिक कार चला रहा था और तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

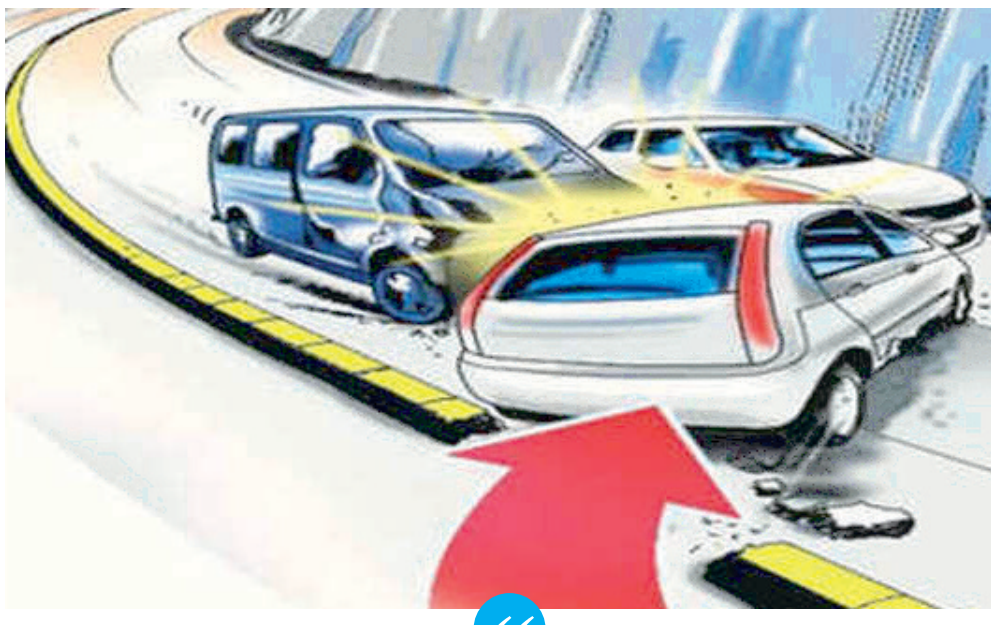

"राज पार्क थाने के अधिकारियों को मंगोलपुरी के एस-ब्लॉक चौक के पास शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि में हादसे की सूचना मिली। पुलिस उपायुक्त (बाहरी) हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जब एक टीम मौके पर पहुंची, तो उन्हें मारुति सुजुकी बलेनो पलटी हुई मिली।

केजरीवाल बोले- दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, 26 झीलों को किया जा रहा विकसित

पश्चिमी दिल्ली में पप्पनकलां लेक का दौरा करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पानी की किल्लत है। इसलिए हम पड़ोसी राज्यों से बात कर रहे हैं। अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में पप्पनकलां लेक का दौरा करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पानी की किल्लत है। इसलिए हम पड़ोसी राज्यों से बात कर रहे हैं। अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और सीवर के पानी को साफ कर जमीनी जल स्तर में सुधार करें। फिर जमीन से पानी निकालकर आरओ से साफ कर भूमिगत जल घर में जमाकर पीने के काम लाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहां पर सात और चार एकड़ के दो लेक हैं। यहां पर पानी को साफ करने का काम किया जा रहा है। एक साल पहले लेक बने थे, यहां पर पानी डालने से आधे किलोमीटर तक जमीनी जल स्तर छह मीटर उपर गया।

दिल्ली में डिवाइडर से टकराकर कार पलटने से युवक की मौत, एक घायल; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

इस पानी को ट्यूबवेल से निकालकर साफ किया जाएगा। इस तरह से पूरी दिल्ली में 26 लेक बना रहे हैं। इसमें 16 कृत्रिम 10 प्राकृतिक लेक को विकसित किया जाए। जब यहां का जमीनी जल ऊपर आएगा तब इसका उपयोग किया जाएगा। ढ़ाई एकड़ से कम क्षेत्र में जलाशय को विकसित किया जाएगा। 35 जलाशय ठीक कर चुके हैं। इस तरह से 380 जलाशय दिल्ली में बनाए जाएंगे।

ब्रीफ न्यूज

कोर्ट में पेश हुआ महाठग: अदालत से बोला सुकेश- 'पक्षपात हो रहा, जज बदल दें', नाराज कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली। सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट में कहा, कि मेरे साथ पक्षपात होता है जज को बदल दिया जाए। उसकी इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। यहां पेशी के दौरान उसने जज पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट में कहा, कि मेरे साथ पक्षपात होता है जज को बदल दिया जाए। उसकी इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सुकेश को कड़ी फटकार लगाई और सुकेश की न्यायिक हिरासत को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।

चेंज को लेकर डिलीवरी ब्वॉय के साथ मारपीट, गुरपाल ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

दिल्ली। आरोप है कि चेंज को लेकर बहस शुरु हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में गुरपाल नाम के एक डिलीवरी ब्वॉय ने राजौरी गार्डन इलाके में चेंज नहीं करने पर कुछ लोगों के खिलाफ उसे और उसके साथी अमन को कथित तौर पर पीटने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोप है कि चेंज को लेकर बहस शुरु हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई।

हरा रंग, ब्लू टिक व फ्रॉड शब्द अब आपकी मेहनत की कमाई बचाएंगे, दिल्ली पुलिस ने उठाया ये बड़ा कदम

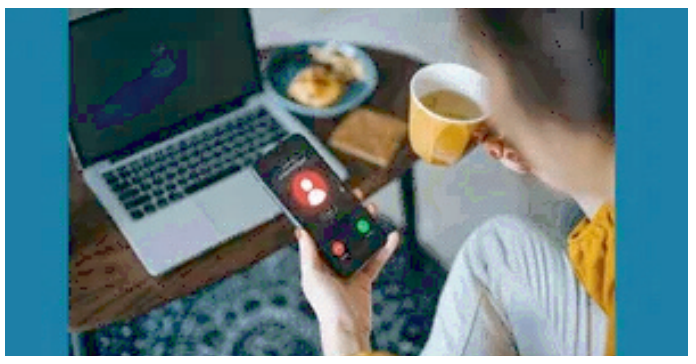

नई दिल्ली। जालसाजों के अभी तक के सभी नंबर टू कॉलर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। लोगों को जालसाजी से बचाने के लिए पुलिस जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी। अब हरा रंग, ब्लू टिक और फ्रॉड शब्द आपकी मेहनत की कमाई को बचाएंगे। जी, हां ये सही है। अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी व कर्मियों का फोन आने पर हरे रंग (ग्रीन बैज) में ब्लू टिक आएगा। जबकि दूसरी तरफ जालसाज फोन करेगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर फ्रॉड या स्पैम शब्द लिखकर आएगा। ऐसे में आप जालसाजों के शिकार होने से बच सकते हैं। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि पुलिस अभी तक के सभी जालसाजों के नंबर टू कॉलर को साझा करेगी। वहीं साइबर जालसाजी से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश भर में वर्ष 2020 से 2022 तक 16 लाख से अधिक साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं। इनमें से 32 हजार से ज्यादा एफआईआर संबंधित मामलों में दर्ज की गई हैं। कोरोना काल में तो साइबर ठगी के मामले और ज्यादा बढ़ गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ पुलिस उपायुक्त प्रशांत प्रिया गौतम ने बताया कि वर्तमान में साइबर जालसाज करीब 13 तरीकों से लोगों ठग रहे हैं। इसमें सेक्सटॉर्शन ज्यादा प्रचलित है।

इसमें जालसाज एक लड़की के माध्यम से पहले पीड़ित को वीडियो कॉल करते हैं और और उसकी अश्लील वीडियो बना लेते हैं। फिर अन्य नंबरों से फोन कर खुद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए कहते हैं वीडियों की पीड़ित लड़की ने खुदकुशी कर ली है और उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। ऐसे में पीड़ित बहुत ज्यादा डर जाता है और मामले को रफा-दफा करने के नाम पर मोटी रकम दे बैठता हैं। इस तरह के बढ़ते मामले को देखते हुए ही दिल्ली पुलिस ने टू कॉलर के साथ ब्लू टिक के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।

स्क्रीन पर ऐसे दिखेंगे पुलिस अधिकारियों के नंबर

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि टू कॉलर अब अपनी दिल्ली पुलिस डायरेक्ट्री सर्विसेज पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों व कर्मियों की मोबाइल नंबर प्रदर्शित करेगा। पुलिस अधिकारियों के सभी सत्यापित नंबरों पर एक हरा बैज और एक नीला टिक मार्क होगा। साथ ही एक सरकारी सेवा टैग हाइलाइट होगा।

जापानी कंपनी का डीलर बनाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, 18 बैंक खाते पुलिस ने किए सीज

दक्षिणी जिले की साइबर थाना पुलिस ने लोगों को मेडिकल सेक्टर में इंवेस्ट कर लाभ कमाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपित ठग की पहचान बदरपुर के कैप्टन के रूप में हुई है।

नई दिल्ली। दक्षिणी जिले की साइबर थाना पुलिस ने लोगों को मेडिकल सेक्टर में इंवेस्ट कर लाभ कमाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपित ठग की पहचान बदरपुर के कैप्टन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के 18 बैंक खातों की पहचान कर उन खातों को सीज कर दिया है।

पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि जिले के साइबर थाने में छह लाख 38 हजार सात सौ रुपए की आनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने आनलाइन उनसे संपर्क किया। उन्हें बताया कि वे जापानी कंपनी के प्रतिनिधि हैं और भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता को आफर दिया कि यदि वे कृष्णा इंटरप्राइजेज से बातचीत करके उन्हें इससे संबंधित कच्चा माल कम दाम में उपलब्ध करा पाएं तो जापानी प्रतिनिधि उन्हें कमीशन देंगे। साथ ही उन्हें भारत में अपनी कंपनी का डीलर बनाने का लालच देकर उनसे उक्त रकम ठग ली। शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपितों द्वारा जिस खाते में ठगी की सारी रकम ट्रांसफर की गई थी, वह बदरपुर स्थित कृष्णा एंटरप्राइजेज के नाम से यूको बैंक में पंजीकृत पाया गया। पुलिस ने खाते से सारी जानकारी खंगाली तो पता चला कि यह खाता कैप्टन नामक व्यक्ति द्वारा खोला गया था। पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारा तो आरोपित वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने मिली जानकारी के आधार पर तकनीकि विशेषज्ञों की मदद से उसे जसोला इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दो आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक मोबाइल फोन बरामद कर लिए। साथ ही पुलिस ने आरोपित के कुल 18 बैंक खातों को भी सीज कर दिया। जिन्हें आरोपित ठगी के लिए उपयोग करता था। पूछताछ के दौरान आरोपित ने पुलिस को बताया कि लोगों को ठगने के लिए उसने अपने तीन सहयोगियों जगपाल, दिलशाद और सूरज के निर्देश पर कई सिम कार्ड खरीदे थे और कई खातों को भी खोला था।

रैपिड मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के पास मिले शव के टुकड़े, महिला है या पुरुष? पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली। सराय काले खां में रैपिड मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक शव मिला है। पुलिस को शव के टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक कॉल मिली थी। जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और फोरेंसिक टीम शव के टुकड़ों को इकट्ठा किया। दिल्ली के सराय काले खां में रैपिड मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक शव मिला है। पुलिस को शव के टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक कॉल मिली थी। जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और फोरेंसिक टीम शव के टुकड़ों को इकट्ठा किया। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि शव किसी महिला का है या पुरुष का।

भारत में राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के लिए करीब 15 करोड़ बजट निर्धारित है।

जागरूकता अभियान पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद अंगदान कम, अब स्पेन की तर्ज पर शुरू होगा TPM कोर्स

स्पेन में अंगदान के प्रति जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाता है। इस कार्य के लिए वहां अलग से कोई बजट भी निर्धारित नहीं होता। फिर भी वहां अंगदान अधिक होता है। जबकि भारत में राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के लिए करीब 15 करोड़ बजट निर्धारित है।

नई दिल्ली। स्पेन में अंगदान के प्रति जागरूकता अभियान नहीं चलाया जाता है। इस कार्य के लिए वहां अलग से कोई बजट भी निर्धारित नहीं होता। फिर भी वहां अंगदान अधिक होता है। जबकि भारत में राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के लिए करीब 15 करोड़ बजट निर्धारित है।

इसलिए जागरूक अभियान में भारी भरकम रकम खर्च होने के बावजूद अभी कैडेवर (ब्रेन डेड) डोनर लोगों का अंगदान कम होता है। अंगदान पर एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें सामने आई। इसलिए अंगदान को बढ़ावा देने के लिए स्पेन की तर्ज पर एम्स में टीपीएम (ट्रांसप्लांट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट) कोर्स शुरू किया गया है।

तैयार होगी पेशेवर टीम

एम्स के न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर डा. दीपक गुप्ता ने बताया कि यह कोर्स शुरू करने का मकसद डाक्टरों को प्रशिक्षित कर अंगदान के लिए प्रतिबद्ध पेशेवर टीम तैयार करना है। देश में वर्ष 1994 में अंगदान के लिए कानून बना। इसके बाद से अब तक किसी भी वर्ष अंगदान का आंकड़ा एक हजार नहीं पहुंच पाया है। पिछले वर्ष देश में ब्रेन डेड हुए 904 लोगों के अंगदान से 2765 अंग प्रत्यारोपित हुए। ब्रेन डेड लोगों का अंगदान कम होने के साथ-साथ अंगों के इस्तेमाल की दर भी बहुत कम है।

एक ब्रेन डेड व्यक्ति से आठ से नौ लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। मौजूदा समय में देश में एक ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगदान से औसतन तीन लोगों को अंग प्रत्यारोपण हो पा रहा है। यहां डाक्टरों में ब्रेन डेड को प्रमाणित करने को लेकर जागरूकता का अभाव है। इसलिए स्पेन सहित अमेरिका, जापान व इटली से 15 डाक्टरों को बुलाकर यह चर्चा की गई कि किस तरह यहां अंगदान को बढ़ाया जा सकता है। जिसमें यह बात सामने आई है कि अंगदान के लिए प्रतिबद्ध डाक्टरों व कर्मचारियों की टीम बनानी पड़ेगी। इसलिए आगे चलकर देश के अन्य अस्पतालों में टीपीएम कोर्स संचालित कर डाक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

स्पेन के डीटीआइ (डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट) फाउंडेशन के डेवलपमेंट डायरेक्टर व बार्सिलोना युनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर च्लोए बैलेस्टे ने बताया कि स्पेन में अंगदान कार्यक्रम में पेशेवर लोगों नियुक्ति है। अंगदान की जिम्मेदारी आइसीयू में नियुक्त डाक्टर लेते हैं। इसलिए सभी अस्पतालों के आइसीयू में एक विशेषज्ञ को अंगदान के लिए अधिकृत किया गया है।

अंगदान संयोजक भी डाक्टर होते हैं। जबकि भारत में अस्पतालों में नियुक्त अंगदान संयोजक डाक्टर नहीं होते। स्पेन में अंगदान के लिए कोई अतिरिक्त बजट नहीं होता है। इसलिए कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया जाता। अस्पताल खुद अंगदान कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। भारत में भी अंगदान को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। एम्स भी इसके लिए प्रयास कर रहा है। अंगदान के लिए सभी अस्पतालों में संचालक मानक प्रक्रिया का होना जरूरी है।

देश में अंग प्रत्यारोपण के आंकड़े

सबसे अधिक प्रत्यारोपण- वर्ष 2022
कुल प्रत्यारोपण- 15,561
इससे पहले अधिक प्रत्यारोपण- वर्ष 2019
कुल प्रत्यारोपण- 12,666
सबसे अधिक लाइव डोनर प्रत्यारोपण
वर्ष 2022- 12,791
वर्ष 2021- 10,638

सबसे अधिक कैडेवर डोनर अंगदान

वर्ष 2016- 930
वर्ष 2022- 904

सबसे अधिक कैडेवर डोनर अंग प्रत्यारोपण

वर्ष 2022- 2765
वर्ष 2016- 2265

प्रति कैडेवर डोनर अंग प्रत्यारोपण

वर्ष 2022- 3.05

200 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपियों ने कर्मचारियों पर लगाया फर्जीवाड़े का आरोप, थाने में 9 केस दर्ज

गाजियाबाद में रेड एप्पल रेजिडेंसी और रेड एप्पल होम्स में आशियाना के नाम 200 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपित आइडिया बिल्डर ने अपने ही कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

गाजियाबाद। रेड एप्पल रेजिडेंसी और रेड एप्पल होम्स में आशियाना के नाम 200 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपित आइडिया बिल्डर ने अपने ही कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर थाना सिहानी गेट में नमन जैन की शिकायत के आधार पर नौ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

राजनगर एक्सटेंशन में इन दोनों प्रोजेक्ट को शुरू कर अलग-अलग कंपनियां बनाकर लोगों से धोखाधड़ी के आरोप में थाना नंदग्राम पुलिस ने राजकुमार जैन और नमन जैन समेत नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। परिवार के सदस्यों पर अभी तक 100 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। इस मामले की विवेचना एसआइटी कर रही है।

नमन जैन के अनुसार, उन्होंने मोरटा में बाहुबली एनक्लेव प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। भाई अक्षय जैन की कंपनी आइडिया बिल्डर्स प्रा. लि. में कार्यरत नंदग्राम के राजेश त्यागी, मेरठ में रोहटा के अमरीश कुमार त्यागी व इसरार अली, मोरटा का अजय त्यागी और राजनगर का नरेंद्र पाल काम करते थे।

अक्टूबर 2021 में आरोपितों ने उनके पिता राजकुमार जैन से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। पैसे नहीं देने पर आरोपितों ने फर्जी मुहर का उपयोग कर उनके प्रोजेक्ट के नौ प्लाट अलग-अलग लोगों को बेच दिए। इसी बीच पुलिस ने उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जमानत मिलने के बाद उन्हें इस फर्जीवाड़े का पता चला। आरोप है कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की, जिसके बाद कोर्ट में याचिका डाली।

नौ मुकदमों में इन कर्मचारियों के अलावा ओमवती त्यागी, संदीप, विरेंद्र गौतम, भूषण त्यागी, चंचल त्यागी, दिनेश कुमार, ब्रजकिशोर त्यागी, पवन कुमार, युगल किशोर त्यागी, सुरेश एमसी, अमित कुमार त्यागी, जगपाल त्यागी, प्रवीण कुमार त्यागी, मनोज कुमार शर्मा, विनोद कुमार व सुशांत त्यागी को फर्जी तरीके से प्लाट खरीदने व गवाह बनने का आरोपित बनाया गया है।

हजारों लोगों का अपने घर का सपना होगा पूरा

गुरुग्राम। वर्ष-2023 की पहली तिमाही में शहर के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में हजारों लोगों का अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है। जिला नगर योजनाकार द्वारा तीन हजार अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट को स्वीकृति देने और हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा इसका पंजीकरण करने के साथ अब सेक्टर-63 में 25 एकड़ के एक प्रोजेक्ट में तीन दिन के अंदर 8 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति की बुकिंग हुई है। सेक्टर-63 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर डीएलएफ ने द आर्बर नाम से बहुमंजिला इमारतों का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें 39 मंजिल की पांच टावर हैं। 1137 यूनिट हैं। डीएलएफ के कार्यकारी निदेशक आकाश ओहरी ने बताया कि प्रोजेक्ट में विदेशी खरीदारों ने भी घर खरीदा है। 95 फीसदी खरीदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने उपयोग के लिए घर खरीदा है। आवासों में प्राकृतिक प्रकाश और ताजी हवा के आवागमन के लिए विशेष ध्यान रखा गया है।

कुछ ही दिन पहले जिला नगर योजनाकार विभाग (डीटीपी) ने तीन हजार अफोर्डेबल यूनिट के लिए स्वीकृति दी है। इसके अलावा हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) से भी इनके लिए पंजीकरण संख्या भी हासिल हुई। तीन हजार परिवारों के लिए 2027 की पहली तिमाही तक घरों को देने का काम शुरू करने का दावा किया जा रहा है। सोहना के सेक्टर-5 में तथास्तु प्रोजेक्ट में 22 एकड़ में 14 टावर्स बनाए जाएंगे। इस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में केवल 3 बीएचके फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। एसटीपी संजीव मान कहते हैं कि शहर में रुके हुए प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो रहा है। नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और उनको अच्छी प्रतिक्रिया मिली रही है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में जटिलताओं को कम करने की जरूरत है। हमने पिछले दिनों संपत्ति की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में पुराने मालिक के फोन पर ओटीपी आने की व्यवस्था को बदलने की मांग की थी। साथ ही आर्किटेक्ट द्वारा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था पर विचार के लिए डीटीपी योजना से भी मुलाकात की थी।

- नरेंद्र यादव, अध्यक्ष, होम डेवलपर्स एवं प्लाट होल्डर्स एसोसिएशन

इनसाइड

इन्फ्लुएंजा के 2 और मरीज मिले

गुरुग्राम। 4 साल के बच्चे को एच-3 एन-2 से संक्रमित पाए जाने के बाद अब जिले में इन्फ्लुएंजा मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान 2 मरीज मिलने का दावा किया है। विभाग ने शहर के लोगों अपील की है कि वे पूर्व की तरह कोरोना की गाइड लाइन का पालन करें व सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। ज्ञात हो हाल के दिनों में एच-3 एन-2 के संक्रमण से अकेले हरियाणा में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आकर लोगों की जांच शुरू की। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को पाए गए दोनों ही मरीज गुरुग्राम के निवासी है। एक एच-3 एन-2 से संक्रमित पाया गया है जबकि दूसरा इन्फ्लुएंजा टाइप- बी से संक्रमित है। एक मरीज निजी अस्पताल में भर्ती था उसे अस्पताल से अब छुट्टी दे दी गई है। जबकि अन्य होम आइसोलेशन में चिकित्सकों की निगरानी में हैं। बता दें कि बीते दिनों संक्रमण की अफवाह के बाद 136 संदिग्ध मरीजों के सेंपल जांच के लिए भेजे गए थे। जिसमें 4 साल का एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया था।

पुराने फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र ऋषि मार्केट स्थित एक पुराने फर्नीचर के गोदाम में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई जिससे गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकलकर्मियों ने तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

गाजियाबाद। गाजियाबाद स्थित लोनी कोतवाली क्षेत्र ऋषि मार्केट स्थित एक पुराने फर्नीचर के गोदाम में शनिवार अलसुबह भीषण आग लग गई। जिससे लाखो की कीमत का पुराना फर्नीचर जलकर खाक हो गया। गनीमत रही की आग की चपेट में कोई नही आया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

ऋषि मार्केट कालोनी में मनोज कुमार का मकान है। मकान को पिछले दो सालों से किराये पर लेकर मनीष ने पुराने फर्नीचरों का गोदाम खोल रखा है। शनिवार सुबह लगभग चार बजे गोदाम में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया।

दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

आग को देख स्थानीय लोगों ने जिसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना पर पहुंची दमकलकर्मियों की 2 गाड़ियों ने तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

फर्जी बिजली विभाग के अधिकारी बन फ्लोर मिल पर मारा छापा, ठगे तीन लाख

मुरादनगर। बिजली विभाग के फर्जी बिजलेंस टीम के अधिकारी बनकर ठगों ने एक फ्लोर मिल पर छापा मारा। ठगों ने 25 लाख रुपये की जुर्माना लगाने की बात कहकर मिल संचालक से तीन लाख रुपये ठग लिए। डीसीपी ग्रामीण जोन के आदेश पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर की है।

राधेश्याम विहार कॉलोनी निवासी राहुल शर्मा नमस्कार आटा नाम से फ्लोर मिल चलाते हैं, मिल चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 13 जनवरी को बिजली विभाग के जेई मिल पर आए और चेकिंग करके चले गए। अगले दिन फिर सात लोग आए और खुद को बिजलेंस टीम से बताया। उन्होंने एक युवक को एसडीओ, एक्शन पीए, जेई, जेएमटी बताया। उन्होंने कहा कि आपने फ्लोर मिल पर अपना ट्रांसफार्मर नहीं लगवाया, जिसके कारण आप पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है, मिल भी सील हो जायेगी। आरोप है कि इसके बाद राहुल शर्मा से पांच लाख रुपये की रसीट कटवाने को कहा, लेकिन तीन लाख रुपये में सौदा तय हुआ, टीम तीन लाख रुपये लेकर चली गई और रसीद गाजियाबाद ऑफिस से प्राप्त करने को कहा गया। बिजली विभाग ऑफिस राहुल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस नाम के कोई अधिकारी काम नहीं करते है। डीसीपी ग्रामीण जोन से पीड़ति ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत की। डीसीपी के आदेश पर पुलिस ने रवि एसडीओ, आदित्य उर्फ दिनेश पीए एक्सन, अर्जुन जेई, तारा जेएमटी, नदीम जेई व दो अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तेज बारिश ने हड़ताल के दौरान किया आग में तेल का काम, कई जगह बिजली आपूर्ति ठप; बढ़ी लोगों की परेशानी

अपनी मांगों के लिए बिजली कर्मचारी बृहस्पतिवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने अन्य विभागों के कर्मचारियों को बिजलीघरों पर तैनात किया था लेकिन विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने के लिए इंतजाम नाकाफी नजर आए।

नई दिल्ली। अपनी मांगों के लिए बिजली कर्मचारी बृहस्पतिवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने अन्य विभागों के कर्मचारियों को बिजलीघरों पर तैनात किया था, लेकिन विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने के लिए इंतजाम नाकाफी नजर आए।

बृहस्पतिवार रात से ही शहर से गांव और करीब दो दर्जन से अधिक हाइराइज सोसायटी में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। उस पर शनिवार सुबह मौसम खराब होने के बाद बारिश ने आग में तेल का काम किया और एक-एक कर जोन के सभी डिवीजन में ब्रेक डाउन की सूचनाएं आने लगी है।

दोपहर दो बजे तक करीब दो दर्जन जगह पर बारिश की वजह से ब्रेक डाउन हुआ। इनमें सुबह 11.40 बजे डिवीजन-2 में 132 केवी राठी स्टील फीडर प्रताप विहार, 132 केवी गोविंदपुरम के शास्त्रीनगर फीडर में दोपहर 1.32 बजे, 132 केवी मोरटा में लोनी से 132 केवी आपूर्ति दोपहर 12.54 बजे से 1.15 बजे तक ठप, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र के 33 केवी फीडर में 1:34 बजे से, 132 केवी लालकुआं के फीडर कविनगर के सीएच स्टील, हिंदुस्तान इंफ्रा, सुची पेपर मिल में दोपहर 1.20 से ब्रेक डाउन के अलावा 33 केवी चिरोरी लोनी लाइन ब्रेकडाउन, 33 केवी फुलेरा लोनी ब्रेकडाउन, 33 केवी सिकरानी लोनी ब्रेकडाउन दर्ज किया गया है।

इससे शहर से देहात क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आपूर्ति ठप है। विद्युतकर्मियों की हड़ताल की वजह से प्रशासन द्वारा लगाए गए अन्य विभाग के कर्मचारियों को फाल्ट तलाश करने में समस्या आ रही है। यही वजह रही कि समय से आपूर्ति सुचारू होने में दिक्कत आ रही है। कई जगह पेयजल आपूर्ति को लेकर लोग परेशान हैं।

चाकू से गोदकर युवक को उतारा मौत के घाट, कब्रिस्तान में अर्धनग्न अवस्था में मिला अज्ञात का शव

बुलंदशहर। पुलिस ने बताया कि चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई है। अभी तक युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिकंदराबाद पुलिस अन्य थानों से भी शव के बारे में जानकारी कर रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान में युवक का अर्धनग्न शव मिला है। पुलिस ने बताया कि चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई है। अभी तक युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिकंदराबाद पुलिस अन्य थानों से भी शव के बारे में जानकारी कर रही है।

दर्दनाक: सिलेंडर से भरा ई-रिक्शा पलटा, घर के बाहर खेल रही दो बच्चियां दबीं, एक की मौत

डासना गेट के पक्की मोरी निवासी आमिर का कहना है कि दिल्ली निवासी उनकी बहन मायके में आई हुई थी। उनकी दोनों भांजी अलीला और आयशा घर के बाहर खेल रही थीं। इसी दौरान सिलेंडर से भरा एक ई-रिक्शा आया जो अनियंत्रित होकर पलट गया।

गाजियाबाद। कोतवाली क्षेत्र डासना गेट में शुक्रवार शाम करीब चार बजे सिलेंडर से भरा ई-रिक्शा बाइक से टकराकर पलट गया। इसी दौरान ई-रिक्शा के नीचे दो मासूम बच्चियां दब गईं। हादसे में छह साल की अलीना की मौत हो गई जबकि उसकी चार साल की बहन आयशा गंभीर रूप से घायल हो गई। उस समय दोनों बच्चियां घर के बाहर खेल रही थीं। मामले में परिजनों ने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। डासना गेट के पक्की मोरी निवासी आमिर का कहना है कि दिल्ली निवासी उनकी बहन मायके में आई हुई थी। उनकी दोनों भांजी अलीला और आयशा घर के बाहर खेल रही थीं। इसी दौरान सिलेंडर से भरा एक ई-रिक्शा आया जो अनियंत्रित होकर पलट गया। ई-रिक्शा पर कमला गैस एजेंसी लिखा हुआ था।

शोर मचते ही मोहल्ले के लोगों ने दोनों बच्चियों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने अलीना को मृत घोषित कर दिया जबकि आयशा की हालत नाजुक बनी हुई है। एसीपी नगर अंशु जैन का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

परांठे के दोगुना रुपये मांगने के विरोध में युवक को जमकर पीटा

गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम क्षेत्र में हापुड़ चुंगी स्थित ढाबे पर परांठे के दो गुना रुपये मांगने का विरोध करने पर ढाबे कै स्टाफ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर अन्य युवकों ने भी पीड़ति युवक पर हाथ साफ कर दिया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति युवक के बाल पकड़े और अन्य लोग उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं। मारपीट की वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो में पीड़ति युवक अपना नाम अंकित राणा बता रहा है। युवक का कहना है कि वह ढाबे पर परांठे खाने आया था। जहां ढाबा संचालक उनसे परांठे के दोगुना रुपये मांगने लगा। विरोध करने पर ढाबे के स्टाफ ने उनकी पिटाई कर दी। उसने जब 112 पर कॉल की तो तीन बार में कॉल नहीं उठी, चौथी बार में पुलिस ने कॉल उठाई तो उन्होंने मामले की जानकारी दी। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान के लिए टीम लगाई गई हैं। मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

इनसाइड

सीनएजी पावरट्रेन के साथ आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कितनी दमदार, चेक करें सभी डिटेल

Maruti Suzuki Brezza CNG भारतीय बाजार में काफी दमदार फीचर्स के साथ आई है। इसमें आपको काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसमें कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं है आज हम आपके लिए इस कार की डिटेल्स लेकर आए हैं।

नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद मार्केट में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने भारत में Maruti Suzuki Brezza CNG को लॉन्च कर दिया है। सीनएजी पावरट्रेन के साथ आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ब्रेजा मारुति की कामयाब गाड़ियों में रही है। Maruti के पास वर्तमान में CNG का सबसे बड़ा लाइनअप है और Brezza CNG इस लिस्ट में शामिल होने वाली नई ब्रांड है। चलिए आपको इस कार से जुड़ी खास डिटेल्स के बारे में बताते हैं।

आपको बता दें, मारुति सुजुकी ने ब्रेजा सीएनजी में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किया है। यह एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्लैट बोनट, स्क्वायर-ऑफ व्हील आर्च और एलईडी टेल लैंप के साथ आती है।

Maruti Suzuki Brezza CNG फीचर्स

भारतीय बाजार में ये कार कई दमदार फीचर्स से लैस होगी। इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज़ कंट्रोल, स्मार्टप्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी सुविधाओं के साथ आएगी, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले, मिश्र धातु के पहिये, कीलेस एंट्री, इंजन को शुरू / बंद करने के लिए पुश बटन और भी बहुत कुछ मिलता है।

Maruti Suzuki Brezza CNG इंजन

Maruti Suzuki Brezza CNG 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड इंजन द्वारा संचालित है जो 98 बीएचपी और 136 एनएम की पीक टॉर्क जनरेट करती है। सीएनजी पर चलने पर पावर घटकर 85 बीएचपी और 121 एनएम हो जाती है। Brezza CNG केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश की जाएगी। ब्रेजा सीएनजी दावा करती है कि इसकी ईंधन दक्षता 25.51 किमी/किग्रा है।

Maruti Suzuki Brezza CNG में हुए ये बदलाव

सीएनजी वाहन होने के नाते, कंपनी ने इस कार में कुछ बदलाव किए हैं। सीएनजी फ्यूल लिड को पेट्रोल फिलर स्पेस में इंटीग्रेट किया गया है। इस कार में बूट स्पेस को दिखाने के लिए सीएनजी सिलेंडर को ढका गया है।

2023 ह्यूंडई वरना की पहली झलक आई सामने, डीलरशिप पर पहुंचने लगीं गाड़ियां

इस महीने 21 तारीख को 2023 Hyundai Verna को लॉन्च किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं। इन तस्वीरों में गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कंपनी इसमें क्या कुछ ऑफर कर सकती है...

नई दिल्ली। कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai अपनी लोकप्रिय सेडान Verna के अपडेटेड वर्जन को 21 मार्च को लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर पर 2023 Hyundai Verna की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके टीजर भी मौजूद हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी ने New Gen Verna को डीलरशिप पर भेजना भी शुरू कर दिया है। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर नजर आ रहा है। क्या कुछ दिखा नई पीढ़ी की Hyundai Verna में, आइए जान लेते हैं...

एक्सटीरियर और इंटीरियर

कंपनी 2023 Hyundai Verna को पुरानी वरना के मुकाबले और अधिक स्पोर्टियर लुक के साथ पेश करने जा रही है। नई पीढ़ी की Verna में हॉरिजेंटल एलईडी पोशिजनिंग के साथ सम्पूर्ण आकार के एलईडी डीआरएल दिए गए हैं। इन बदलावों के साथ Hyundai की इस सेडान कार का लुक और फील पूरी तरह से बदल जाएगा।

इसके फ्रंट में मल्टी बैरल एलईडी लाइट के साथ पैरामैट्रिक ग्रिल डिजाइन को दिया गया है। वहीं इसके रियर में एजी (edgy) हेडलैंप के साथ एलईडी लाइट बार का इस्तेमाल किया गया है।

डायमेंशन

2023 Hyundai Verna अपने लंबे व्हीलबेस, अच्छी लंबाई और चौड़ाई की वजह से अच्छा रोड प्रेजेंस हासिल करेगी। नई वेर्ना की लंबाई 4,535 मिमी, चौड़ाई 1,765 मिमी और ऊंचाई 1,475 मिमी होगी। New Gen Verna में 528 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है। ओवरऑल बात करें तो पुरानी वरना के मुकाबले नई पीढ़ी की Verna और आकर्षक हो गई है।

फीचर्स

2023 Hyundai Verna में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जा सकता है। साथ ही इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, हॉरिजॉन्टल एसी वेंट्स, लेयर्ड डैशबोर्ड, हीटिंग के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स और वेंटिलेशन जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है।

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ADAS के साथ EBD, ABS, ECS, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल-स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं।

इंजन

कंपनी नई Verna में दो 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन देगी। एक नैचुरली एस्पिरेटेड होगा, वहीं दूसरा टर्बो यूनिट। शक्ति की बात करें तो नैचुरल एस्पिरेटड 115 एचपी वहीं टर्बो इंजन 160 एचपी की पॉवर वाला होगा। इन दोनों इंजन में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। नैचुरल एस्पिरेट इंजन में CVT और टर्बो-पेट्रोल का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

डब्ल्यूटीआई कैब्स इंडिया को 100 वाहनों की आपूर्ति करेगी एमजी मोटर्स इंडिया, सूची में शामिल हैं हेक्टर और जेडएस ईवी

WTi Cabs India इंडिया अपनी फ्लीट में हेक्टर और जेड एस ईवी सहित MG Motors India की कुल 100 कार शामिल करने जा रही है। दोनो ही कंपनियों की ओर से ये जानकारी दी गई है।

कैब सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी डब्ल्यूटीआई कैब्स इंडिया MG Motors India से कुल 100 कार लेने जा रही है। इन 100 कारों की सूची में MG Motors India की Hector और ZS EV जैसी कार शामिल हैं। कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि इन कार को रेंट-ए-कार डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे संबंधित जानकारी देते हुए MG Motors India के सीनियर डायरेक्टर सेल्स राकेश ने कहा, "हमारी साझेदारी एमजी के वाहनों को भारत में एसयूवी और ईवी के प्रति उत्साही लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाएगी। हम एमजी हेक्टर और जेडएस ईवी को अपनी पसंद के वाहन के रूप में चुनने के लिए डब्ल्यूटीआईकैब्स के बहुत आभारी हैं।₹

MG Motors से 100 वाहनों को अपनी फ्लीट में शामिल करने की घोषणा करते हुए कंपनी के सीईओ अशोक वशिष्ठ ने कहा कि, "स्थायी गतिशीलता प्रदान करने के हमारे निरंतर प्रयास में हम अपने बेड़े में ईवी को जोड़ते रहेंगे। हमारा प्रयास हमारे कॉर्पोरेट ग्राहकों को टिकाऊ और मजबूत गतिशील समाधान प्रदान करना है।₹ साथ ही उन्होने कि हमारी कंपनी एमजी मोटर इंडिया से निरंतर बिक्री और सेवाओं के समर्थन के लिए तत्पर है।

MG की ZS EV और Hector दोनों ही भारतीय बाजार में पॉपुलर हैं। एक ओर Hector डीजल और पेट्रोल दोनों पॉवरट्रेन के साथ आती है वहीं MG ZS एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है। कीमत की बात करें तो कंपनी ZS EV को 23.38 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचती है।वहीं MG Hector को कंपनी 15 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचती है। MG Hector SUV 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ही विकल्पों के साथ उपलब्ध है। बाजार में 7-सीटर वाली हेक्टर MG Hector Plus के नाम से जानी जाती है।

इस महीने कई कारें हो सकती हैं बंद, कंपनियां दे रहीं इन पर बंपर डिस्काउंट

BS6 फेज II एक अप्रैल 2023 बीएस 6-II उत्सर्जन मानकों के अनुरूप ही कारों को बनाएगी। जिसके कारण कीमत में बढ़ोतरी होगी और कुछ कंपनियां अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए कई ऑर्फस भी दे रही है।

मार्च अब खत्म ही होने वाला है, इसके साथ ही ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना भी है। इस महीने के बाद कई चीजें बदल जाएगी। एक तरह के कहे तो 1 अप्रैल से कई नियम लागू होने वाला है। इनमें से एक नियम BS6 फेज II का नए एमिशन नॉर्म्स का है। इसके चलते कई कारें बंद होने वाली है। इसके चलते सभी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी कारों के इंजन को अपडेट कर रही है।

इसके कारण कारों की कीमत भी बढ़ने वाली है। हालाकिं कई कंपनियों ने तो अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी करनी भी चालू कर दी है। इसके बाद जिन मॉडल्स की ब्रिकी सेल्स में कम है, उनको तो कंपनी बंद ही कर रही है। वहीं कुछ कंपनियां अपने स्टॉक को खाली करने के लिए शानदार डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं।

भारतीय बाजार में होंडा अपने 5 मॉडल बंद करने वाली है। इसमें शामिल होंडा सिटी 4th जेन, सिटी 5th जेन (डीजल), अमेज (डीजल), जैज और WR-V। वहीं कंपनी ने इसका प्रोडक्शन पहले ही बंद भी कर दिया था।

भारतीय बाजार में महिंद्रा लोगों के दिलो पर आज से ही नहीं कई सालों से राज करते आ रही है। कंपनी अपने कुछ मॉडल्स को बंद करने वाली है। मराजो, अल्टुरस G4 और KUV100 है। कंपनी इसके स्टॉक को खाली करने के लिए 70 हजार रुपये का ऑफर दे रही है।

भारतीय बाजार में हुंडई अपनी 2 कारों को बंद करने वाली है। वो अपनी वरना (डीजल) और अल्काजार (डीजल) को बंद करेगी। कंपनी अपने स्टॉक को खाली करने के लिए 1.25 लाख रुपए तक का बेनिफिट दे रही है।

कंपनी अपनी दो कारों को बंद करने वाली है। ये दोनों मॉडल पेट्रोल से चलने वाले हैं। इसके कारण ही कंपनी इनको अपडेट नहीं कर रही है और जल्द से जल्द अपने स्टॉक को खाली करने वाली है। इसके लिए कंपनी 55 हजार रुपये का ऑफर प्रदान करा रही है।

इस हफ्ते टू-व्हीलर मार्केट में हुआ बहुत कुछ नया

हीरो ने उतारा इलेक्ट्रिक स्कूटर तो होंडा ने लॉन्च की बाइक

इस हफ्ते भारतीय बाजार में बहुत सारी बाइक लॉन्च हुईं। इस लेख में हम आपको 100 सीसी Honda Shine से लेकर Kawasaki Z900 RS तक में हुए अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं।

नई दिल्ली। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार बहुत बड़ा है। आए दिन यहां कुछ न कुछ नया होता ही रहता है। आज के इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस हफ्ते भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में क्या नया आया, पढ़िए पूरी खबर...

पल्सर NS 200 और NS 160 हुई अपडेट

देश की पॉपुलर दोपहिया कंपनी बजाज ने इस हफ्ते NS 200 और NS 160 को नए बदलावों के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने नई बजाज पल्सर NS160 की एक्स-शोरूम कीमत 1.35 लाख रूपए और NS200 की एक्स-शोरूम कीमत 1.47 लाख रुपए रखी है। बदलाव की बात करें तो इन दोनों बाइक में कंपनी ने अपडेट डुअल-चैनल ABS सिस्टम और अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क सेटअप ऑफर किया है।

आ गई 100 सीसी में Honda Shine

जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक Honda Shine को 100 सीसी इंजन के साथ लॉन्च किया है। इसका सीधा मुकाबला हीरो की 100 सीसी वाली बाइक स्प्लेंडर प्लस से होगा। कंपनी इसे 64,900 रूपए (एक्स-शोरूम, मुंबई) की कीमत पर बेचेगी।

Kawasaki Z900 RS हुई अपडेट

Kawasaki ने ZX-10 R की लॉन्चिंग के बाद इस हफ्ते 2023 Kawasaki Z900 RS को भी भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसे ऑउटगोइंग मॉडल के मुकाबले 51 हजार रुपए महंगा कर दिया गया है। अब इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 8.93 लाख रुपए है। बदलाव की बात करें तो इसमें नई कलर स्कीम, अपडेटेड पॉवरट्रेन के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, TFT स्क्रीन, इंस्ट्रूमेंट कलस्टर और ब्लूटूथ क्नेक्टिविटी जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं।

नई Interseptor 650 और Continental GT हुई लॉन्च

इस हफ्ते Royal Enfield ने अपनी दो 650 सीसी वाली बाइक को अपडेट के साथ पेश किया है। कंपनी ने 2023 इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 को कई अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है। दोनों बाइक की कीमत की बात करें तो नई Interseptor 650 3.03 लाख रुपए और Continental GT 3.19 लाख रुपए (एक्स-शोरूम चेन्नई) की कीमत पर उपलब्ध है।

ये भी हैं नए अपडेट

इस हफ्ते हुए अन्य लॉन्च की बात करें तो हीरो इलेक्ट्रिक ने अपने Optima और NYX रेंज के इलेक्ट्रिक स्कूटरों को नए ढंग से पेश किया है। KTM ने भी इस हफ्ते 1290 Super Duke की भारतीय बाजार में वापसी कराई है। देश के उभरते इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड ने इसी हफ्ते Ola S1 Pro के Limited Holi Edition के पेश किया।

प्रदेश के लिए ग्रोथ एजेंडे की प्रासंगिकता

संजय शर्मा

उद्यमी का खून चूस कर सरकार को अपनी आय नहीं बढ़ानी है, बल्कि उसके साथ खड़े होकर प्राप्त लाभ का उचित अंश टैक्स के रूप में सरकार के कोष में जाना चाहिए...

''भारतीय उद्योग परिसंघ'' (सीआईआई) ने इस बार अपने वार्षिक अधिवेशन में दिनांक 7 मार्च को शिमला में मुख्यमंत्री को अध्यक्षता का न्योता दिया। गत वर्षों की भांति मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर मिला, परंतु इस बार मात्र आयोजन की औपचारिकताएं नहीं थी, अपितु मुख्यमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आने वाले पांच वर्षों का सरकार का एजेंडा हिमाचल के विकास के लिए स्पष्ट किया। ऐसा महसूस हुआ कि यह एजेंडा प्रदेश की नैसर्गिक क्षमताओं, कमियों, आने वाले अवसरों व बाधाओं की पहचान कर गहराई से विश्लेषण करने के पश्चात तय किया गया है। मुख्यमंत्री के संबोधन में, जो वह कह रहे थे, उसे चरणबद्व तरीके से पूर्ण करने का एक विश्वास व प्रतिबद्धता स्पष्ट झलक रही थी, जिसकी वहां उपस्थित उद्यमियों ने मुक्तकण्ठ से सराहना की। हिमाचल के बारे में बात करने पर सामने आता है- यहां का शांत, स्वच्छ वातावरण, कसी हुई कानून व्यवस्था, जनता का कमोबेश कानून के प्रति आदर, सरप्लस व गुणवत्तायुक्त बिजली, सौहार्दपूर्ण लेबर मैनेजमेंट संबंध, प्रशासन तक सहज पहुंच आदि जो निवेशकों को और दूसरे बड़े राज्यों की स्थिति देखते हुए हिमाचल में निवेश करने को प्रेरित करते हैं। परन्तु साथ ही जब कनैक्टिविटी की बात हो, ट्रक यूनियन की समस्या हो, औद्योगिक निवेश के लिए जमीन लेने में ''धारा 118'' की पेचीदगियां आती हों, कच्चे माल व बाजार की परेशानियां हों, लगभग 20-22 सरकारी विभागों की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए प्रयासों की बात हो, औद्योगिक बस्तियों में समुचित सामाजिक अधोसंरचना का विकसित न होना आदि कारणों से शायद उद्यमी यहां निवेश से पहले हर पहलू पर विचार अवश्य करता है। इस अधिवेशन में सरकार की ओर से आमंत्रित प्रतिनिधियों ने पिछली सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश के वित्तीय दिवालियेपन की ओर जाने, 75000 करोड़ के कर्ज के बोझ, वर्तमान में 11000 करोड़ की देनदारियों आदि का जिक्र भी किया गया, परंतु इन डराने वाले आंकड़ों के बावजूद मुख्यमंत्री ने सबको आशान्वित किया कि यद्यपि आने वाले समय में प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, परन्तु उन्होंने फिर कहा कि छोटी सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनका मानना है कि आज ''सरवाइवल ऑफ दि फिटैस्ट'' का युग है, जो परिस्थितियों से लडना जानता है, वही अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। प्रदेश सरकार के मुखिया का यह कथन उद्यमियों में भी सकारात्मकता का संचार करेगा।

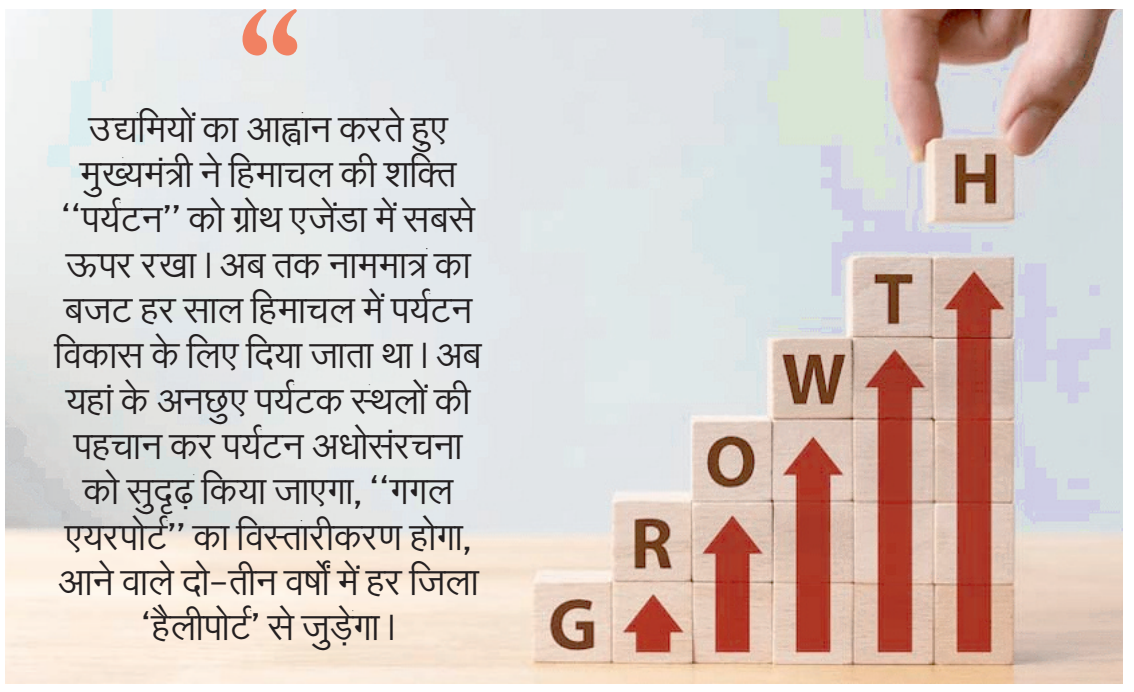

उद्यमियों का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमाचल की शक्ति ''पर्यटन'' को ग्रोथ एजेंडा में सबसे ऊपर रखा। अब तक नाममात्र का बजट हर साल हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए दिया जाता था। अब यहां के अनछुए पर्यटक स्थलों की पहचान कर पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा, ''गगल एयरपोर्ट'' का विस्तारीकरण होगा, आने वाले दो-तीन वर्षों में हर जिला 'हैलीपोर्ट' से जुड़ेगा। कांगड़ा जिला को ''पर्यटन राजधानी'' के रूप में विकसित किया जाएगा, पौंग डैम जो अब तक सरकारी नियम-कानूनों के कारण उपेक्षित सा था, वहां नियमों में ढील देकर शिकारा, बोटिंग, जलखेल आादि को विकसित किया जाएगा। कांगड़ा में थीम पर्यटन, गोल्फ कोर्स, रोप-वे, अंतरराष्ट्रीय स्तर का चिडियाघर व साहसिक पर्यटन को बढावा दिया जाएगा। मकसद यह है कि पूरे हफ्ते चौबीसों घंटे पर्यटन गतिविधियां कैसे चलें ताकि पर्यटक यहां की सुविधाओं व नैसर्गिक सौंदर्य से अभिभूत हो बार-बार यहां आने को लालायित हो सके। एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा प्रदेश में ''हरित क्रांति'' लाना है- अर्थात राज्य को एक ''ग्रीन राज्य'' के रूप में विकसित करना है, जिसमें ''ग्रीन हाइड्रोजन'' की एक अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर उद्यमियों को आश्वास्त किया कि अभी 'सपना' सा प्रतीत होने वाला यह विषय दो-तीन वर्षों में पूरा होगा। सरकार इस संबंध में इस क्षेत्र के बड़े-बड़े उद्यमियों के साथ समझौता करेगी। आगामी तीन वर्षों में 2500 परिवहन की बसें ई-वाहनों से बदली जाएंगी। 4-5 ''ग्रीन-कॉरीडोर'' बनाए जाएंगे, जगह-जगह सुलभ स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। शायद इतना स्पष्ट एजेंडा '' ग्रीन राज्य'' बनाने का किसी और राज्य का नहीं है। निश्चित रूप से सरकार के इस प्रयास से 'पर्यटन विकास' और 'पर्यटन निवेश' को और पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री ने अगला महत्वपूर्ण एजेंडा ''उद्यमियों'' को एक ''भयमुक्त निवेश प्रदेश'' देना बताया।

अपने मांगपत्र में सीआईआई ने अन्य मसलों के अलावा एक अति संवेदनशील विषय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, वह है- सत्ता में प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम पर उद्यमियों का ''शोषण'' व ''जबरन वसूली'', जिसे बहुत गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उद्यमियों को अपने उद्बोधन में आश्वासन दिया कि यदि किसी उद्यमी के साथ इस प्रकार का वाक्या पेश आता है तो उनके मोबाइल पर संदेश भेज दें, वे स्वयं उससे शीघ्र संपर्क साधेंगे और आरोप सही सिद्ध होने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे दोषी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। उनका मानना है कि निवेश तभी आएगा, जब उद्यम, उद्यमी व उसके कर्मियों को प्रदेश में सुरक्षा का एहसास हो। सरकार की नीतियों व कार्य पद्धति के प्रति उद्यमी का विश्वास होना बहुत आवश्यक है। उद्यम लगेगा तो रोजगार सृजित होगा व टैक्स के रूप में सरकार की आय होगी। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि निवेश के लिए आवश्यक उचित माहौल उपलब्ध करवाया जाए। यदि उद्यमी अपना समय पटवारी, तहसीलदार के कार्यालयों में व सरकारी अनुमतियां लेने में ही लगाएगा तो उसकी परियोजना समय पर कैसे लगेगी? उसकी परियोजना लागत भी बढ़ेगी और सरकार को जो आय होनी है, उसे मिलने में भी विलंब होगा, अतः प्रस्तावित नई ''निवेश नीति'' के अंतर्गत सरकार चाहती है- ''आओ, लगाओ, कमाओ और हिमाचल को भी खिलाओ''। मुख्यमंत्री की परिकल्पना है कि ''नई औद्योगिक नीति'' में उद्यमियों को और सरकार दोनों को अपना-अपना धर्म ईमानदारी से निभाने वाली भावना दिखेगी। उद्यमी का खून चूस कर सरकार को अपनी आय नहीं बढ़ानी है, बल्कि उसके साथ खड़े होकर प्राप्त लाभ का उचित अंश टैक्स के रूप में सरकार के कोष में जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि सरकार की वर्तमान कमजोर माली हालत के दृष्टिगत ''आर्थिक प्रोत्साहनों'' के मुकाबले प्रक्रियाओं, नियमों का सरलीकरण किया जाएगा।

संपादक की कलम से

राज्यपाल फिर सवालिया

सर्वोच्च अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राज्यपाल की भूमिका, दायित्व और सदन में बहुमत साबित करने के आदेश सरीखे पहलुओं पर एक तार्किक बहस को सुना है और सभी पक्षों को सचेत भी किया है। बुनियादी संदर्भ महाराष्ट्र के अघाड़ी गठबंधन की सरकार का है। चूंकि शिवसेना में विधायकों के एक बहुमती गुट ने बगावत की थी, नतीजतन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन राज्यपाल के हस्तक्षेप से बगावती गुट और भाजपा ने साझा तौर पर सरकार बना ली। आज वही सरकार कार्यरत है। उद्धव ठाकरे गुट के वकीलों ने ऐसी सरकार को 'असंवैधानिक' करार दिया है, जबकि न्यायाधीशों का सवाल है कि उस सरकार को कैसे बहाल किया जा सकता है, जिसके मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? बहरहाल संविधान पीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन राज्यपाल की भूमिका एक बार फिर सवालिया हुई है।

महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब रमेश बैस नए राज्यपाल हैं। इसके अलावा, तेलंगाना राज्यपाल को भी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। वहां राज्यपाल ने बीते सितंबर से 7 पारित विधेयकों को स्वीकृति नहीं दी है। वह विधानसभा में पारित बजट पर भी मुहर नहीं लगा रही हैं। यह उनका जानबूझ कर किया जाने वाला व्यवहार है। यकीनन यह असाधारण, संविधान से इतर स्थिति है। संविधान ने इस संदर्भ में राज्यपाल के विशेषाधिकारों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। राज्यपाल किसी भी समय-सीमा तक बिलों पर कुंडली मार कर बैठ सकते हैं। यह कौन-सी संवैधानिक शक्ति हुई? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का विवाद भी सर्वोच्च अदालत में है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी है कि आपसी बातचीत का स्तर बिल्कुल निचले स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए। दोनों संवैधानिक पदों के बीच ऐसी होड़ नहीं लगनी चाहिए। बहरहाल तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी 'मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल' की स्थितियां हैं। टकराव बेहद गहरे हैं, जबकि विवाद संवैधानिक नहीं है। दोनों पदों के बिना हमारा संघीय ढांचा कारगर ही नहीं हो सकता।

विडंबना और दुर्भाग्य है कि राज्यपाल विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों में ही 'परोक्ष राजनीति' खेलते दीखते हैं। दरअसल हमारी सियासत को एहसास होना चाहिए कि अब ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेशी भारत नहीं है। भारत आज स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक संविधान वाला देश है।

राज्यपाल की भी एक निश्चित और संवैधानिक भूमिका है। एक उदाहरण चुनाव आयोग के फैसले और अनुशंसा का है। आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर अपना फैसला बंद कवर में राज्यपाल को भेजा था। तत्कालीन महामहिम ने करीब 6 माह तक उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। अंततः फरवरी में राज्यपाल बैस महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिए गए। नतीजतन आयोग का महत्वपूर्ण फैसला लटक कर रह गया। पश्चिम बंगाल में भी 'मुख्यमंत्री बनाम गवर्नर' के द्वंद्व जारी रहे। दोनों के ट्वीट-युद्ध सार्वजनिक होते रहे। अब वह राज्यपाल देश के उपराष्ट्रपति हैं। बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल के तमाम मामले सर्वोच्च अदालत में ही जाते रहेंगे, अदालत फटकार लगाती रहेगी और मामले सुलझाने पड़ेंगे? यह लोकतंत्र नहीं है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के माकूल माहौल है।

प्रणाली

बजट की अखियों से

बजट की अखियों से हिमाचल को देखता यथार्थ अगर नए संसाधन खोज रहा है, तो वाटर सेस संबंधी अध्यादेश को मिली विधानसभा सदन की पूर्ण सहमति का आलेख अवश्य ही आत्मनिर्भरता की सुर्खी लिख रहा है। करीब 172 विद्युत परियोजनाओं के खाते से राजस्व आपूर्ति का अनुमान अगर चार हजार करोड़ के आंकड़े में आर्थिक सपने देख रहा है, तो इस सफर की मंजिल पर सरकार का नाम होगा। जाहिर है ऐसे कदमों के निशान दूर तक देखे जाएंगे और इसीलिए पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के जश्न में खलल पड़ा है। हिमाचल में उत्पादित बिजली अगर पानी के हिसाब से सेस देने लगी, तो यह प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक अधिकार है और यह यहां तक ही नहीं रुकेगा। इसके भीतर विस्थापन की सिसकियों का भी हिसाब है, जो वर्षों से आंसुओं की कीमत चुका रही हैं। जाहिर है पंजाब पुनर्गठन और बीबीएन की आर्थिक हिस्सेदारी में आज तक हिमाचल को छोटा मान कर किनारे लगाया गया, लेकिन वाटर सेस की पैमाइश से कई अन्य द्वार भी खुलेंगे। पंजाब शायद यह कहने की कोशिश कर रहा कि 'आप पहले ऐसे तो न थे'। कल इसी तरह के मुद्दों को जगा कर अगर सुक्खू सरकार केंद्र में बंधक अपने अधिकारों को मुक्त कराने का विकल्प तैयार कर लेती है, तो फिर यही कहा जाएगा कि 'आप पहले ऐसे तो न थे।' पानी के बाद जंगल उगाने की लागत और अपनी ही जमीन पर विकास के लिए जमीन खोजने की तकलीफ से जूझ रहे हिमाचल को या तो इसकी आर्थिक भरपाई चाहिए या जंगल के अधीन केवल पचास प्रतिशत भूमि ही रखने का अध्यादेश चाहिए। प्रदेश की आर्थिकी के लिए हर संकल्प को जमीन चाहिए और यह तभी संभव होगा जब वन संरक्षण अधिनियम के तहत न्याय और विकास का अध्याय मिले। सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए बजटीय प्रावधान तो कर रही है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण का सच फिर यही बता रहा है कि राज्य के संसाधन वेतन भुगतान, पेंशन अदायगी और उधार के चक्रव्यूह से जूझने में ही जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के हर पहलू में अव्वल आता हिमाचली नागरिक समाज इतना समृद्ध प्रतीत होता है, जो राष्ट्रीय आंकड़ों में प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक ऊपर पहचान बना रहा है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर 2,22,227 तक पहुंच रहा है, तो इसके अर्थों में यहां बीपीएल संबंधी योजनाएं तो बंद हो जानी चाहिएं। प्रति व्यक्ति आय के सामने प्रदेश के ऊपर बढ़ते कर्ज के बोझ का मूल्यांकन करें तो प्रदेश घने कोहरे में खड़ा कांप रहा है, जबकि नागरिक खुशहाली की धूप में आनंद ले रहा है। बेशक प्रति व्यक्ति आय औसत के तराजू पर कहीं अधिक और कहीं कम भी माप रही होगी, लेकिन हिमाचल में अति समृद्ध परिवारों की कमी नहीं और यह राज्य के संसाधनों में बंटती मेहरबानियों के सलीके में देखी जा सकती है। जिस प्रदेश में अति उपजाऊ जमीनें बंदरों ने उजाड़ दी हों, वहां कृषि आर्थिकी में दर्ज सकल घरेलू उत्पाद को किस आर्थिक चक्की पर देखें, जबकि थैलियों में आयतित आटे ने नागरिकों की उपभोक्ता मांग बढ़ा दी है। उत्तर भारत के जिलों में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े चकित करते हैं, क्योंकि 2019-20 में किन्नौर 3.14 लाख प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से चमक रहा था, जबकि औद्योगिक तरक्की के हिसाब से सोलन 5.40 लाख प्रति व्यक्ति आय दर्शा रहा था। सबसे नीचे कांगड़ा की प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में मात्र 1.25 लाख रही है।

राहुल पर लगे आरोप मात्र चुनावी स्टंट

योगेन्द्र योगी

विभिन्न वैश्विक रिपोर्टों में जाहिर भारत की स्थिति से मुंह नहीं फेरा जा सकता। इन रिपोर्टों पर भारत की आलोचना को दबाया नहीं जा सकता। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इस मामले में सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसे पूरे विश्व में देखा गया कि कैसे भारत में आवाज बुलंद करने पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कानून की समीक्षा पूरी होने तक देशद्रोह का कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा इतना कमजोर नहीं है कि राहुल गांधी के बयान देने मात्र से दागदार हो जाए। राहुल गांधी के लगाए आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश से या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करानी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ सकती है, अन्यथा ऐसे मामलों को चुनावी राजनीति के स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं माना जा सकता'

आजादी के बाद देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहला मौका आया जब सत्तारूढ़ दल ने संसद ठप की हो। संसद की यह कार्यवाही कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी से माफी मंगवाने की मांग को लेकर बाधित रही। संसद सत्र का प्रति मिनट खर्चा ढाई लाख रुपए आता है। अर्थात एक दिन भी यदि संसद की कार्यवाही ठप रहती है तो करोड़ों का नुकसान होता है। इसकी भरपाई सांसद या मंत्री नहीं करते, बल्कि देश के आम करदाताओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। राहुल ने लंदन की कैमब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में भारत में संस्थाओं के नियंत्रण में होने और अपने फोन की जासूसी किए जाने का आरोप लगाया। राहुल ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कराए जाने का मुद्दा उठाया। आरएसएस को एक फासीवादी संगठन और भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में बताते हुए विदेशी हस्तक्षेप की मांग की।

भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया है। गौरतलब है कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। संसद में जो हुआ उसे पुरी दुनिया ने देखा। सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार राहुल के बयान को इतना गंभीर मानती है तो उनके खिलाफ देश के अपमान और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराती। इसका फैसला अदालत कर लेगी कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है या नहीं। इससे भाजपा का बचना यह दर्शाता है कि देश के अपमान और देशद्रोह को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। हकीकत में इस मामले में भाजपा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती है। सवाल यह भी है कि भाजपा राहुल गांधी से तो चुनावी तरीके से निपट लेगी किन्तु वैश्विक संस्थाओं द्वारा विभिन्न मामलों में देश की हालत की जो तस्वीर बताई गई है, भाजपा उनसे कैसे निपटेगी। भाजपा ने ऐसी संस्थाओं से कभी माफी मांगने और उन देशों को चेतावनी देते हुए संबंधों में दरार पडने की बात कभी नहीं की।

अलबत्ता केंद्र सरकार उन रिपोर्टों को भारत की छवि खराब करने वाले बताता हुए खारिज करती रही है। विगत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व स्तर की रैंकिंग प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट में भारत की जो तस्वीर पेश की है, वह देश को शर्मसार करने वाली रही है। केंद्र की भाजपा सरकार विश्व में विभिन्न मामलों में जारी रिपोर्टों को खारिज तो कर सकती है, पर माफी नहीं मंगवा सकती, जिनके कारण भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत छह पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में वल्ड हैपीनेस इंडेक्स में शामिल कुल 146 देशों में भारत 136वें पायदान पर है। रिपोट्र्स विदआउट बॉडर्स की ओर से जारी वल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत 142वें स्थान पर बरकरार है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस का दंभ भरने वाली सरकार की दृढ़ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2021 के वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान 85वां रहा। मानव विकास सूचकांक में पिछले वर्ष भारत 131वें स्थान पर था और वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में भारत का स्थान फिसलकर 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर पहुंच गया।

इसी तरह भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में सामने आया कि पिछले साल भारत का स्थान 115 था और अब वह दो स्थान और नीचे चला गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स-2022 में भारत को शांति के मामले में लो कैटेगरी में रखा गया है। इस रैंकिंग में भारत 3 स्टेप चढक़र अब 135वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा इंडेक्स-2021 में 113 देशों के बीच 71वां स्थान हासिल किया। विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वें स्थान पर है। विश्व में होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं में 11 प्रतिशत मृत्यु भारत में होती हैं। जबकि दुनिया के वाहन का महज एक प्रतिशत ही हमारे यहां है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 73535 बच्चे गायब हो गए। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो गायब होने वाले बच्चों की संख्या 340000 है। पिछले 5 सालों से हर साल औसतन 68000 बच्चे गायब होते रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी 59263 बच्चे गायब हो गए थे। गायब होने वाले बच्चों में 75 फीसदी लड़कियां होती हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की इंटरएक्टिव वेबसाइट हाल्ट दि हेट के मुताबिक भारत में 2016 के बाद से कथित हेट क्राइम की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। अकेले 2019 के पहले छह महीनों में ऐसे अपराधों की 181 घटनाएं वेबसाइट की ओर से दर्ज की गईं। महिलाओं के लिए सडक़ सुरक्षा, महिलाओं की जानबूझकर हत्या, गैर-साथी यौन हिंसा, अंतरंग साथी यौन हिंसा, कानूनी भेदभाव, वैश्विक लिंग अंतर, लिंग असमानता और महिलाओं के प्रति हिंसा में खतरे का सूचकांक वल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2022 की एक रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर है। वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वे में भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बताया गया था। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा हुए सर्वे में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीडऩ और उन्हें सेक्स वर्कर के धंधे में जबरन धकेलने के कारण भारत को सबसे असुरक्षित देश माना गया। वर्ष 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ।

विभिन्न वैश्विक रिपोर्टों में जाहिर भारत की स्थिति से मुंह नहीं फेरा जा सकता। इन रिपोर्टों पर भारत की आलोचना को दबाया नहीं जा सकता। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इस मामले में सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसे पूरे विश्व में देखा गया कि कैसे भारत में आवाज बुलंद करने पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कानून की समीक्षा पूरी होने तक देशद्रोह का कोई नया केस दर्ज नहीं होगा।

> एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की इंटरएक्टिव वेबसाइट हाल्ट दि हेट के मुताबिक भारत में 2016 के बाद से कथित हेट क्राइम की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। अकेले 2019 के पहले छह महीनों में ऐसे अपराधों की 181 घटनाएं वेबसाइट की ओर से दर्ज की गईं।

चिंतन विचार

रूस और अमेरिकी संबंध और बिगड़े तो विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जायेगा

अशोक मधुप

एक साल से ज्यादा से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अब यह साबित हो गया कि नाटो देश यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को सबक सिखाना चाहते हैं। उसे तोड़ना चाहते हैं। उनका इरादा रूस की अकड़ खत्म करने का है।

एक साल से ज्यादा से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटों के दखल को देख शायद रूस ने अब इनसे ही सीधे सुलटने का निर्णय ले लिया है। वह इस तरह की पहले से इसकी चेतावनी देता भी रहा है। लगता है कि इसकी शुरुआत उसने कालासागर में अमेरिकी ड्रोन को मार कर कर दी है। उसने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को एक तरह से चेतावनी भी दे दी है। अपने इरादे भी बता दिए हैं। घटना को लेकर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका रूस की जासूसी कर रहा है। इसी वजह से ये घटना हुई। रूसी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका ने कोई उकसावे की कार्रवाई की तो रूस भी उसका 'उचित जवाब' देगा।

एक साल से ज्यादा से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अब यह साबित हो गया कि नाटो देश यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को सबक सिखाना चाहते हैं। उसे तोड़ना चाहते हैं। उनका इरादा रूस की अकड़ खत्म करने का है। यह खुद तो नहीं लड़ रहे किंतु युद्धरत यूक्रेन की अस्त्र/शस्त्र और अन्य प्रकार की पूरी क्षमता से मदद करने में लगे हुए हैं। रूस भी हालत को समझ गया है। उसने पीठ पीछे की कहानी को आगे करने का निर्णय लिया। इसी के तहत रूस ने काला सागर के ऊपर उड़ते अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। उसकी ये कार्रवाई बताती है कि उसने अमेरिका और नाटो देशों से अब सीधे निपटने का फैसला कर लिया है। अच्छा है कि नाटो अब भी संभाल जाए। सुधर जाए। रूस के दुश्मन यूक्रेन की परोक्ष और अपरोक्ष रूप से की जाने वाली मदद बंद कर दें। ऐसा न होने पर वह नाटो देशों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई कर सकता है। यूक्रेन एक छोटा-सा देश है। रूस जैसी महाशक्ति से उसका कोई मुकाबला नहीं। यूक्रेन नाटो में शामिल होने के प्रयास में लगा था। रूस चाहता था कि यूक्रेन नाटो गठबंधन में शरीक न हो। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को रूस का हिस्सा मानते रहे हैं। पुतिन की सदा मंशा रही कि वो रूस को साल 1991 से पहले यानि सोवियत संघ के विघटन से पहले वाले स्वरूप में वापस लेकर आएं। यूक्रेन रूस का हिस्सा बन जाए। वह ऐसा नहीं कर पाए। उधर यूक्रेन नाटों में शामिल होने के प्रयास में लग गया। इससे उन्हें लगा कि यदि ऐसा हो गया तो नाटो की सेनाएं यूक्रेन में आ जाएंगी। यूक्रेन की और रूस की सीमा सटी है। नाटो की सेनाएं यूक्रेन में आकर रूस के लिए परेशानी ही पैदा करेंगी। साथ ही उसकी यूक्रेन के रूस में मिलाने की योजना भी धूसरित हो जाएगी।

यूक्रेन पूरी क्षमता से नाटो में शामिल होने के प्रयास में लगा था। रूस के मना करने की अपील का उस पर असर नजर नही आ रहा था। ऐसे में उसे सबक सिखाने में लिए रूस ने ये हमला किया। उसने इसे छोटा सैन्य आपरेशन नाम दिया। रूस ने हमला ये सोचकर किया कि यूक्रेन के नाटों में शामिल होने के बाद नाटो देश उसका साथ देंगे, पहले नहीं, किंतु एक साल से चल रहे युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका और नाटो देश खुद युद्ध नहीं लड़ रहे, अपितु वे यूक्रेन को युद्ध लड़ा रहे हैं। मदद कर रहे हैं। खुद युद्ध के मैदान में नही हैं किंतु हथियार और गोला बारूद उनका है। सिर्फ लड़ने वाले उनके सैनिक नहीं हैं। वे सिर्फ यूक्रेन के जवान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, तकरीबन 30 देशों ने भारी तादाद में यूक्रेन को हथियार और जरूरी चीजें मुहैया कराईं। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने भी ऐलान किया है कि यूक्रेन को विध्वंसकारी टैंक जैसे- 'चैलेंजर 2 टैंक' और 'लेपर्ड 2 टैंक' यूक्रेन को मुहैया कराये जाएंगे। यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 90 स्ट्राइकर भेजे हैं। इसके अलावा, अमेरिका ने यूक्रेन को 59 ब्रेडली इन्फैंट्री लड़ाकू विमान भेजे हैं। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका लगातार अपने हथियारों का जखीरा यूक्रेन को दे रहा है। गौरतलब है कि रूस लगातार यह बात कहता आया है कि यह युद्ध यूक्रेन के अलावा अमेरिका भी लड़ रहा है।

रूस लंबे समय से अमेरिका और नाटो देशों को चेतावनी दे रहा है कि यूक्रेन की मदद की तो ठीक नहीं होगा। वह मदद को सीधा अपने पर हमला मानेगा। कई बार वह परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की धमकी भी देता रहा है। यह भी कहा है कि किसी देश की सैटलाइट उनके देश की जासूसी करती मिली, तो वह उस सैटलाइट को मार गिराएगा। अमेरिका और नाटो देशों की कोशिश थी कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर कर दिया जाए।

विपणन वर्ष 2022-23 में 15 मार्च तक चीनी उत्पादन मामूली घटकर 2.81 करोड़ टन पर

पी.वी. न्यूज

चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि में लगभग 336 चीनी मिलें चालू थीं, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में चालू चीनी मिलों की संख्या 438 थी।

नई दिल्ली। देश का चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष में 15 मार्च तक मामूली कमी के साथ दो करोड़ 81.8 लाख टन रह गया। उद्योग निकाय इस्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। विपणन वर्ष 2021-22 की समान अवधि में चीनी उत्पादन दो करोड़ 84.5 लाख टन का हुआ था। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि में लगभग 336 चीनी मिलें चालू थीं, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में चालू चीनी मिलों की संख्या 438 थी।

उद्योग निकाय ने बयान में कहा, एथनॉल उत्पादन के लिए उपयोग (डायवर्जन) के बाद देश का चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष 2022-23 के अक्टूबर-15 मार्च के दौरान दो करोड़ 81.8 लाख टन था। देश में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन चालू विपणन वर्ष में अक्टूबर से 15 मार्च के दौरान घटकर एक करोड़ 1.9 लाख टन रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह एक करोड़ नौ लाख टन था।

इस्मा ने बयान में कहा कि देश के तीसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में भी उत्पादन मामूली गिरावट के साथ 53.5 लाख टन रह गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 55.4 लाख टन का हुआ था। देश में चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन चालू विपणन वर्ष में 15 मार्च तक मामूली रूप से बढ़कर 79.6 लाख टन का हुआ, जो एक साल पहले की समान अवधि में 78.3 लाख टन रहा था। अन्य राज्यों में उत्पादन पहले के 41.8 लाख टन की तुलना में थोड़ा बढ़कर 46.8 लाख टन का हुआ।

इस्मा ने कहा कि उक्त अवधि में लगभग 31.1 लाख टन चीनी को एथनॉल उत्पादन के लिए उपयोग में लाया गया है। जनवरी में इस्मा ने अक्टूबर, 2022 में जारी 3.65 करोड़ टन के अपने पहले के अनुमान के मुकाबले वर्ष 2022-23 के लिए अपने चीनी उत्पादन अनुमान को घटाकर 3.4 करोड़ टन कर दिया। विपणन वर्ष 2021-22 में चीनी उत्पादन 3.58 करोड़ टन का हुआ।

तीन दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह डेयरी उद्योग सम्मेलन को किया संबोधित

पी.वी. न्यूज

गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डेयरी क्षेत्र का योगदान 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

नई दिल्ली। इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि डेयरी उद्योग छोटे किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डेयरी क्षेत्र का योगदान 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। 45 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। हमारी दूध प्रसंस्करण क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। 1970 से 2022 तक भारत की जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है और हमारे डेयरी क्षेत्र के कारण हमारा दूध उत्पादन 10 गुना बढ़ा है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के आजादी से अब तक के डेयरी उद्योग के विकास को देखें तो सारे पहलुओं को हमारी डेयरी सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के साथ जोड़ने के लिए काम किया है। इसमें हमारी सहकारी डेयरी का योगदान बहुत बड़ा है।

रविवार को गृह मंत्री जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे और जूनागढ़ में एपीएमसी दौलतपारा स्थित कृषि शिविर में एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। शाह बाद में सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप के लॉन्च के साथ विभिन्न विकास कार्यों का ई-उद्घाटन करेंगे। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद शाह की दो दिवसीय गुजरात यात्रा का समापन होगा।

सरकार की विशेष इस्पात के लिए पीएलआई 2.0 पेश करने की योजना: सिंधिया

केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'विशेष इस्पात समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 6,322 करोड़ रुपये की योजना के तहत निवेश के लिए चुनी गई कंपनियों ने हिस्सा लिया। सरकार की देश में मूल्यवर्धित इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दूसरा संस्करण शुरू करने की योजना है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'विशेष इस्पात समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 6,322 करोड़ रुपये की योजना के तहत निवेश के लिए चुनी गई कंपनियों ने हिस्सा लिया।

सिंधिया ने विशेष इस्पात के लिए पीएलआई के पहले संस्करण के भागीदारों से कहा, ''इस्पात उद्योग के इतिहास और भविष्य में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। पीएलआई 1.0 पूर्ण विराम नहीं है, यह यात्रा की शुरुआत है। हमारा मंत्रालय पहले से ही पीएलआई 2.0 पर विचार कर रहा है।'' मंत्री ने आगे उद्योग के हितधारकों से अपने सुझाव और प्रतिक्रिया साझा करने के लिए भी कहा ताकि विशेष इस्पात के लिए अगली पीएलआई योजना जल्द से जल्द तैयार की जा सके।

इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि इस योजना को इच्छुक पक्षों से जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है और यह उद्योग के परिदृश्य को बदलने वाली साबित होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई, 2021 में देश में विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी।

इनसाइड

पहली ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन, जानें कितने करोड़ हुए हैं खर्च

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली भारत-बांग्लादेश ऊर्जा पाइपलाइन का शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच यह पहली सीमापार पाइपलाइन है। इसे लगभग 377 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। कुल कीमत में 285 करोड़ रुपये बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में खर्च हुए हैं। यह राशि भारत ने अनुदान सहायता के तहत खर्च की है।

 # पाइपलाइन से एक साल में 10 लाख टन हाई-स्पीड डीजल भेजा जा सकेगा

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 18 मार्च शाम पांच बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये से भारत-बांग्लादेश मित्र पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। पाइपलाइन से एक साल में 10 लाख टन हाई-स्पीड डीजल को भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में हाई-स्पीड डीजल भेजा जाएगा।

 # सरकार बोली ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग और बढ़ेगा

सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) को भारत से बांग्लादेश ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीका स्थापित होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग और बढ़ेगा।

श्रीलंका से आ रहे यात्रियों को बंगलुरु एयरपोर्ट पर गलत जगह पर छोड़ा, परेशान रहे यात्री

नई दिल्ली। सीआईएसएफ और इमिग्रेशन के साथ टर्मिनल ऑपरेशंस टीम को सतर्क कर दिया गया और यात्रियों को तुरंत आव्रजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर ले जाया गया। इसके बाद यात्री अंतरराष्ट्रीय बैगेज एरिया की ओर रवाना हो गए। कल श्रीलंकाई एयरलाइंस यूएल 173 से यात्रा करने वाले 30 यात्रियों को गलती से अंतरराष्ट्रीय आगमन बस गेट के बजाय बेंगलुरु हवाई अड्डे के घरेलू आगमन बस गेट पर छोड़ दिया गया था। बीआईएएल के प्रवक्ता के अनुसार इससे यात्री अंतरराष्ट्रीय की जगह घरेलू बैगेज एरिया में पहुंच गए। हालांकि, सीआईएसएफ और इमिग्रेशन के साथ टर्मिनल ऑपरेशंस टीम को सतर्क कर दिया गया और यात्रियों को तुरंत आव्रजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर ले जाया गया। इसके बाद यात्री अंतरराष्ट्रीय बैगेज एरिया की ओर रवाना हो गए। इस दौरान यात्री परेशान दिखे। बीआईएएल के प्रवक्ता ने बताया कि यह एक मानवीय भूल थी जिसके कारण यह भ्रम पैदा हुआ। उन्होंने कहा इस मामले में सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

गवर्नर ने डिजिटल भुगतान में शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता व सामर्थ्य पर दिया जोर, कही ये बात

शक्तिकांत दास ने कहा कि पारंपरिक बैंक शाखा मॉडल एक भौतिक स्थान प्रदान करता है जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, डिजिटल भुगतान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहां उपयोगकर्ताओं को कभी-कभी अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए उचित मंच का पता लगाने में मुश्किल होती है। उन्होंने कहा, ₹लोगों को अपनी शिकायतों को हल करने में जितना संघर्ष करना पड़ता है, उससे इस बात की संभावना बढ़ती है कि वे भविष्य में डिजिटल भुगतान का प्रयास करने से बचेंगे।

शक्तिकांत दास ने कहा कि पारंपरिक बैंक शाखा मॉडल एक भौतिक स्थान प्रदान करता है जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, डिजिटल भुगतान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहां उपयोगकर्ताओं को कभी-कभी अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए उचित मंच का पता लगाने में मुश्किल होती है।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को डिजिटल भुगतान में त्वरित शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता और सामर्थ्य के महत्व पर जोर दिया। शनिवार को कोच्चि में भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) सम्मेलन में बोलते हुए, गवर्नर ने कहा, ₹डिजिटल भुगतान में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए त्वरित शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता और सामर्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शक्तिकांत दास ने कहा कि पारंपरिक बैंक शाखा मॉडल एक भौतिक स्थान प्रदान करता है जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, डिजिटल भुगतान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहां उपयोगकर्ताओं को कभी-कभी अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए उचित मंच का पता लगाने में मुश्किल होती है। उन्होंने कहा, ₹लोगों को अपनी शिकायतों को हल करने में जितना संघर्ष करना पड़ता है, उससे इस बात की संभावना बढ़ती है कि वे भविष्य में डिजिटल भुगतान का प्रयास करने से बचेंगे। गवर्नर ने कहा कि पीएसओ की ओर से लेनदेन का त्वरित मिलान ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने का एक आसान और त्वरित तरीका है। उन्होंने कहा कि शून्य से न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ शिकायतों के नियम-आधारित समाधान का समर्थन करने के लिए नवीनतम तकनीकों का भी लाभ उठाया जा सकता है।

TCS के नये CEO को ग्राहक आपूर्ति दोगुना होने का भरोसा

वह ग्राहक आपूर्ति बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं। टीसीएस के छह साल से सीईओ रहे राजेश गोपीनाथन ने बृहस्पतिवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। गोपीनाथन के दूसरे कार्यकाल में चार साल से अधिक का समय बाकी था। वह 15 सितंबर को अपना पद छोड़ देंगे।

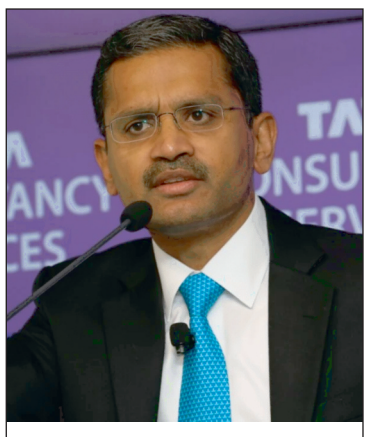

कंपनी ने कहा कि उसके बीएसएफआई श्रेणी के अध्यक्ष कृतिवासन तत्काल प्रभाव से सीईओ के रूप में कंपनी का नेतृत्व करेंगे। बीएसएफआई श्रेणी का इस समय कंपनी की आय में 31.5 प्रतिशत का योगदान है।

नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के मनोनीत मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के कृतिवासन ने शुक्रवार को कहा कंपनी की कार्य संस्कृति में नए प्रमुख के कार्यभार संभालने पर महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव नहीं होते हैं। वह ग्राहक आपूर्ति बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं। टीसीएस के छह साल से सीईओ रहे राजेश गोपीनाथन ने बृहस्पतिवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। गोपीनाथन के दूसरे कार्यकाल में चार साल से अधिक का समय बाकी था। वह 15 सितंबर को अपना पद छोड़ देंगे।

कंपनी ने कहा कि उसके बीएसएफआई श्रेणी के अध्यक्ष कृतिवासन तत्काल प्रभाव से सीईओ के रूप में कंपनी का नेतृत्व करेंगे। बीएसएफआई श्रेणी का इस समय कंपनी की आय में 31.5 प्रतिशत का योगदान है। गोपीनाथन (52 वर्ष) ने कहा कि वह 27 साल पहले टाटा इंडस्ट्रीज और 22 साल पहले टीसीएस से जुड़े थे और इस दौरान उन्होंने कभी भी नौकरी बदलने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि, उन्होंने 15 सितंबर के बाद की अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं किया।

कृतिवासन ने शुक्रवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा, टीसीएस की कार्य संस्कृति में यह नहीं है कि अगर कंपनी को कोई नया प्रमुख मिलता है तो उसमें आमूल-चूल रणनीतिक बदलाव हों। हम ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम जारी रखेंगे। बाजार की मांग को देखते हुए बदलाव होंगे। उन्होंने कहा, वन टीम की हमारी संस्कृति बनी रहेगी। उन्होंने कहा, कंपनी में जब कोई नया सीईओ आता है तो हम रणनीतिक रूप से नहीं बदलते हैं। लेकिन हम अपने ग्राहकों के अनुसार बदलेंगे। उन्होंने कहा, मैं आपूर्ति को दोगुना करने की उम्मीद करता हूं।

एसवीबी व सिग्नेचर की तरह और 186 बैंक खतरे में हैं, रिपोर्ट में जाहिर की गई आशंका

जानकारों का मानना है कि सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता बढ़ती ब्याज दरों और गैर-बीमाकृत जमा से उत्पन्न जोखिमों का एक उदाहरण है। दरों के बढ़ने से बैंक की परिसंपत्तियों का मूल्य कम हो गया और घबराए ग्राहकों ने अपनी गैर-बीमाकृत जमा राशि तेजी से निकालनी शुरू कर दी।

रिपोर्ट में कहा गया, 'भले ही गैर-बीमित जमाकर्ताओं में से केवल आधे ही निकासी का फैसला लें पर इससे 186 से 190 बैंकों के बीमाकृत जमाकर्ताओं को भी नुकसान का संभावित खतरा है।

नई दिल्ली। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बढ़ती ब्याज दरों और गैर-बीमित जमा के उच्च अनुपात के कारण अमेरिका में 186 बैंकों पर विफलता का खतरा मंडरा रहा है। सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क पर '2023 में मौद्रिक सख्ती और अमेरिकी बैंक नाजुकताः मार्क-टू-मार्केट लॉस एंड अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर रन्स?' शीर्षक से जारी इस शोध में फेडरल रिजर्व के दर-वृद्धि अभियान के दौरान व्यक्तिगत बैंकों की परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

अध्ययन में बैकों की उन जमाओं की भी जांच की गई जो 2,50,000 डॉलर से अधिक हैं और नियमों के अनुसार बीमित नहीं हैं। अध्ययन के अनुसार ढाई लाख डॉलर से अधिक जमा वाले गैरबीमित निवेशकों में अगर आधे ने भी इन 186 बैंकों से जल्दबाजी में पैसे निकाल लिए तो बीमित जमाकर्ताओं को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी स्थिति होने पर बैंकों के पास सभी जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में एफडीआईसी को दखल देना पड़ सकता है।

अर्थशास्त्रियों को आशंका- 300 अरब डॉलर की बीमित जमा राशि भी खतरे में पड़ सकती है

हालांकि यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शोध में हेजिंग पर कोई विचार नहीं किया गया जो बैंकों को बढ़ती ब्याज दरों के दुष्प्रभाव से बचा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया, 'भले ही गैर-बीमित जमाकर्ताओं में से केवल आधे ही निकासी का फैसला लें पर इससे 186 से 190 बैंकों के बीमाकृत जमाकर्ताओं को भी नुकसान का संभावित खतरा है। ऐसा होने से 300 अरब डॉलर की बीमाकृत जमाराशि भी खतरे में होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गैरबीमित जमा राशि की तेज निकासी जारी रही तो कई बैंक खतरे में पड़ सकते हैं।

सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता बढ़ती ब्याज दरों और गैर-बीमाकृत जमा से उत्पन्न जोखिमों का एक उदाहरण है। दरों के बढ़ने से बैंक की परिसंपत्तियों का मूल्य कम हो गया और घबराए ग्राहकों ने अपनी गैर-बीमाकृत जमा राशि तेजी से निकालनी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि बैंक अपने जमाकर्ताओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा और उसे बंद करने की नौबत आ गई। अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी कि है कि 186 बैंकों को सरकारी हस्तक्षेप या पुनर्पूंजीकरण की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी हालत एवीबी या सिग्नेचर बैंक जैसी हो सकती है। रिपोर्ट में बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्रोतों के विविधीकरण को महत्वपूर्ण माना गया है।

अदालत ने IRDA से कहा, विकलांग व्यक्तियों के लिए बीमा पॉलिसी पेश करें कंपनियां

अदालत ने कहा कि ऐसी बीमा पॉलिसी के परीक्षण के बाद उन्हें शीघ्रता से मंजूरी दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि फरवरी में जारी इरडा के परिपत्र के बाद अब बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विकलांग व्यक्तियों के लिए पॉलिसी की पेशकश करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) से कहा कि वह बीमा कंपनियों से विकलांग व्यक्तियों के लिए पॉलिसी लाने को कहे। अदालत ने कहा कि ऐसी बीमा पॉलिसी के परीक्षण के बाद उन्हें शीघ्रता से मंजूरी दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि फरवरी में जारी इरडा के परिपत्र के बाद अब बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विकलांग व्यक्तियों के लिए पॉलिसी की पेशकश करें। न्यायमूर्ति सिंह ने पिछले साल नियामक को विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्पादों को तैयार करने के लिए सभी बीमा कंपनियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। उन्होंने अपने आदेश में कहा, "परिपत्र के संदर्भ में कंपनियों को विकलांग व्यक्तियों के लिए एक उत्पाद पेश करना है... ऐसा आने वाले वक्त में करना है। हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है।" अदालत ने कहा कि उसके पिछले निर्देशों के अनुसार इरडा ने एक बैठक बुलाई और 27 फरवरी, 2023 को एक आदर्श नीति के साथ विकलांग व्यक्तियों के संबंध में परिपत्र जारी किया। अदालत विकलांगता से पीड़ित कुछ व्यक्तियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने बीमा प्रदाताओं से स्वास्थ्य बीमा कवरेज की मांग की थी।

ईडी ने हुगली जिले में की छापेमारी, स्कूलों में नौकरी घोटाले मामले में कार्रवाई

नईदिल्ली। ईडी ने निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु बनर्जी की परिसपंत्तियों की तलाश में शनिवार को हुगली जिले में छापेमारी की। कार्रवाई स्कूली नौकरियों के एवज में नकदी के कथित घोटाले की जांच के तहत की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु बनर्जी की परिसपंत्तियों की तलाश में शनिवार को हुगली जिले में छापेमारी की। कार्रवाई स्कूली नौकरियों के एवज में नकदी के कथित घोटाले की जांच के तहत की गई। जानकारी के मुताबिक, ईडी जांच दल को कम से कम छह भागों में बांटा गया। टीम ने शनिवार सुबह से पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बालागढ़, बांदेल, चिनसुराह एवं अन्य क्षेत्रों में शांतनु बनर्जी की कथित संपत्तियों पर छापा मारा। एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल शांतनु की इन संपत्तियों के अंदर से ज्यादा कुछ नहीं मिला है। बांदेल और चिनसुराह में दो फ्लैट के ताले हमें तोड़ने पड़े। आरोपी के नाम पर पंजीकृत एक अतिथि गृह के मुख्य द्वार का ताला भी तोड़ा गया। हालांकि, ईडी को ऐसा कुछ नहीं मिला, जो जांच को अगले स्तर पर ले जाने में मददगार हो। तलाशी अभियान अब भी जारी है। दरअसल, शांतनु बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में हैं। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के शीघ्र बाद ही उन्हें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था।

राहुल गांधी के समर्थन में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा

कहा- जब उन्होंने गल्ती नहीं की तो माफी क्यों मांगेगे?

तृणमूल सांसद ने कहा कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेता संसद में कह चुके हैं कि संसद चलाना सरकार का काम है तो यहां भी सरकार को काम करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद बहुत सी बातें बाहर विदेश में कहीं हैं, उन बातों से बहुत लोगों को अपमानित महसूस हुआ है।

नई दिल्ली। संसद में जारी हंगामे के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया है। शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। दरअसल, भाजपा राहुल गांधी के लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर उनसे माफी की मांग कर रही है। इसको लेकर संसद में भी जबरदस्त हंगामा है। हालांकि, शत्रुघ्न सिन्हा इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है तो माफी क्यों मांगेंगे? संसद में हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब सत्तारूढ़ दल ने व्यवधान पैदा किया है।

तृणमूल सांसद ने कहा कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेता संसद में कह चुके हैं कि संसद चलाना सरकार का काम है तो यहां भी सरकार को काम करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद बहुत सी बातें बाहर विदेश में कहीं हैं, उन बातों से बहुत लोगों को अपमानित महसूस हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो गया। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने कहा माफी नहीं मांगेंगे, जब उन्होंने गल्ती नहीं की तो माफी क्यों मांगेगे? हालांकि, राहुल गांधी प्रकरण को लेकर तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से अपना अलग स्टैंड रख रही है।

अब तक तृणमूल कांग्रेस ने खुलकर राहुल गांधी का ना तो समर्थन किया है ना विरोध किया है। वे अपने मुद्दे पर राजनीति कर रही है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने पार्टी नेताओं की एक बैठक के बाद शुक्रवार को यहां कहा कि पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों से दूरी बनाए रखते हुए अपने रास्ते पर चलेगी। बंदोपाध्याय ने हालांकि कहा कि पार्टी ''फिलहाल तीसरे मोर्चे की बात नहीं कर रही और चेतावनी दी कि कांग्रेस को यह नहीं मानना चाहिए कि वह विपक्ष की 'बिग बॉस' है।

सीआरपीएफ की 93वीं बटालियन पर सीबीआई की रेड, अनिमियतताओं की जांच के लिए पहुंची केंद्रीय एजेंसी

सीआरपीएफ सूत्रों का कहना है कि इस बटालियन के शीर्ष अफसर कमांडिंग अफसर को लेकर बल मुख्यालय को उनके व्यवहार को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं। जिसके बाद शनिवार सुबह सीबीआई की 13 लोगों की टीम ने 93वीं बटालियन पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने शनिवार सुबह लखनऊ स्थित 93वीं बटालियन पर छापेमारी की। सीआरपीएफ सूत्रों का कहना है कि इस बटालियन के शीर्ष अफसर कमांडिंग अफसर को लेकर बल मुख्यालय को उनके व्यवहार को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं। जिसके बाद शनिवार सुबह सीबीआई की 13 लोगों की टीम ने 93वीं बटालियन पर छापेमारी की।

महाराष्ट्र में किसानों ने वापस ली अपनी पदयात्रा, मांगों पर विचार होने पर किया फैसला

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक विनोद निकाले ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की सभी मांगों पर राज्य विधायिका में विचार किया गया तथा जमीनी स्तर के अधिकारियों को सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन का आदेश मिल गया है।

नासिक जिले के डिंडोरी से हजारों किसानों एवं आदिवासियों ने अपनी मांगों के समर्थन में पिछले रविवार को अपनी पदयात्रा शुरू की थी।

मुंबई। पैदल ही मुंबई की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी किसानों एवं आदिवासियों ने शनिवार को अपनी पदयात्रा वापस ले ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक विनोद निकाले ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की सभी मांगों पर राज्य विधायिका में विचार किया गया तथा जमीनी स्तर के अधिकारियों को सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन का आदेश मिल गया है। उन्होंने कहा, '' इसलिए हम अपनी पदयात्रा वापस ले रहे हैं।'' नासिक जिले के डिंडोरी से हजारों किसानों एवं आदिवासियों ने अपनी मांगों के समर्थन में पिछले रविवार को अपनी पदयात्रा शुरू की थी। उनकी मांगों में प्याज किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राहत, किसानों को 12 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा कृषि ऋण की माफीशामिल हैं। ये प्रदर्शनकारी ठाणे जिले के वासिंड शहर पहुंच चुके थे जो मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर है।

'राहुल गांधी किस बात के लिए माफी मांगे ?', अशोक गहलोत बोले- संसद को चलने से रोक रही बीजेपी

अशोक गहलोत ने कहा कि संसद शुरू होनी चाहिए, और चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है और आपने लोकसभा में माइक्रोफोन बंद कर दिया? आज जिस तरह से देश तानाशाही का सामना कर रहा है, हर जगह स्थिति बहुत गंभीर है।

नई दिल्ली। लोकतंत्र को लेकर लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गय बयान पर बवाल जारी है। भाजपा इसको लेकर राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। सड़क से संसद तक यह मुद्दा गर्म है। संसद में इस मुद्दे पर भाजपा राहुल से माफी की मांग कर रही है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इससे इनकार किया जा रहा है। इन सब के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी पहली पार्टी है जो संसद को चलने से रोक रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी को किस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए? पीएम मोदी ने जर्मनी और कोरिया में भारत के खिलाफ कई बातें कही हैं। किससे माफी मांगनी चाहिए? पूरी दुनिया देख रही है।

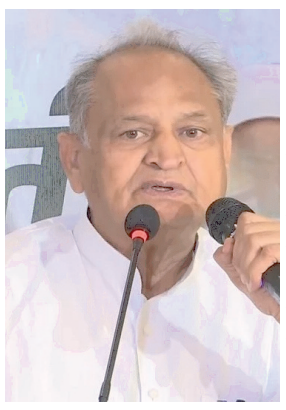

अशोक गहलोत ने कहा कि संसद शुरू होनी चाहिए, और चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है और आपने लोकसभा में माइक्रोफोन बंद कर दिया? आज जिस तरह से देश तानाशाही का सामना कर रहा है, हर जगह स्थिति बहुत गंभीर है। गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि वो(राहुल गांधी) माफी किस बात की मांगे? उनके पहले तो PM मोदी को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब भी वो(राहुल गांधी) बोलना चाहते हैं उन्हें मौका दिया जाता है लेकिन संसद और भारत के बारे में झूठ फैलाना अच्छी बात नहीं है। उन्हें संसद में आकर सांसदों, स्पीकर और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

इससे पहले अपने एक बयान को लेकर संसद में जारी गतिरोध पर राहुल गांधी ने कहा कि देश में अगर लोकतंत्र बरकरार है तो उन्हें संसद में अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ सरकार के चार मंत्रियों ने सदन के भीतर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए एक इम्तहान भी होगा कि उन्हें भी चार मंत्रियों की तरह ही सदन में बोलने का पूरा अवसर मिलता है या फिर चुप होने के लिए कहा जाता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडाणी समूह से जुड़े मामले से ध्यान भटकाने के लिए सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से संसद में पूरा तमाशा खड़ा किया गया है।

'जिस रफ्तार से सफ़ाई का काम चल रहा है लगता है, सेंचुरी भी पूरी हो जाएगी, यूपी में एनकाउंटर पर बोले राजनाथ

रक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने एक जगह पढ़ा कि अब तक यूपी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी मारे जा चुके हैं, यदि अपराधी पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कदम उठाना स्वाभाविक है। जिस रफ्तार से सफाई का काम हो रहा है उससे लगता है कि सेंचुरी भी पूरी हो सकती है।

लखनऊ में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि आज का यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छह वर्ष पूरे कर रहे है। वे प्रदेश के सबसे अधिक समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का डॉ. संपूर्णानंद जी का रिकार्ड पहले ही तोड़ चुके है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार बड़ा दावा करती है। खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिखे। दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि छह साल के कार्यकाल में 10,713 मुठभेड़ों में 5,967 अपराधियों को पकड़ा गया, जबकि 1,708 अपराधी घायल हुए। इसी को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने एक जगह पढ़ा कि अब तक यूपी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी मारे जा चुके हैं, यदि अपराधी पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कदम उठाना स्वाभाविक है। जिस रफ्तार से सफाई का काम हो रहा है उससे लगता है कि सेंचुरी भी पूरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि भय और अपराध के वातावरण से मुक्त होकर आज उत्तर प्रदेश की जनता वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना पाल चुकी है। रोड मैप बन रहा है। काम भी साथ-साथ चल रहा है

लखनऊ में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि आज का यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छह वर्ष पूरे कर रहे है। वे प्रदेश के सबसे अधिक समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का डॉ. संपूर्णानंद जी का रिकार्ड पहले ही तोड़ चुके है। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह से योगीजी ने काम किया है उससे आप परिचित हैं। मैं किसी न्यूज पोर्टल पर देख रहा था। शीर्षक लगा था 'अब तक 63'। पता चला कि पिछले छह वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 63 दुर्दान्त अपराधियों को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश विकास और कल्याणकारी योजनाओं का साक्षी बन रहा है।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि मेरा मानना है कि लखनऊ का इन्फ्रास्ट्रक्चर आज उस स्तर का बन चुका है कि यहां बड़े-बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट आयोजित किए जा सकें। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर Global Investors Meet का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 2020 में यहां एक भव्य Defence Expo भी आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि आने वाले समय में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले National Games या अन्य बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने का दावा किया जाना चाहिए।

भारत विरोधी गैंग में शामिल हैं कुछ रिटायर्ड जज

कानून मंत्री बोले- जूडिशिरी और सरकार के बीच पैदा कर रहे गलतफहमी

पी.वी. संवाददाता

रिजिजू ने कहा कि कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो कार्यकर्ता हैं और एक भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं जो न्यायपालिका को विपक्षी दलों की तरह सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश ₹भारत विरोधी गिरोह₹ का हिस्सा हैं और न्यायपालिका को एक विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि हाल ही में न्यायाधीशों की जवाबदेही पर एक संगोष्ठी हुई थी। लेकिन किसी तरह पूरी संगोष्ठी बन गई कि कैसे कार्यपालिका न्यायपालिका को प्रभावित कर रही है। रिजिजू ने कहा कि कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो कार्यकर्ता हैं और एक भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं जो न्यायपालिका को विपक्षी दलों की तरह सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्रविरोधी कारगुजारी का अंजाम जरूर भुगतेंगे।

कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और कहते हैं कि कृपया सरकार पर लगाम लगाएं। यह तो हो नहीं सकता। न्यायपालिका तटस्थ है और न्यायाधीश किसी समूह या राजनीतिक संबद्धता का हिस्सा नहीं हैं। रिजिजू ने जोड़ते हुए कहा कि ये लोग खुले तौर पर कैसे कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को सरकार का सामना करना चाहिए? कानून मंत्री दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोल रहे थे।

रिजिजू ने कहा कि अगर राहुल गांधी या कोई भी कहता है कि भारतीय न्यायपालिका को हाईजैक कर लिया गया है या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है ' न्यायपालिका मर चुकी है, इसका क्या मतलब है? भारतीय न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए सोच-समझकर प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि दिन-ब-दिन वे यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भारतीय न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है।

विभिन्न संस्थानों के बीच संवैधानिक ₹लक्ष्मण रेखा₹ का आह्वान करते हुए, रिजिजू ने पूछा कि क्या न्यायाधीश प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बनते हैं, जो न्यायिक कार्य करेंगे। यह बयान चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च के फैसले के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में था।

बच्चों का यौन शोषण करने के आरोपी तमिलनाडु का पीएचडी छात्र गिरफ्तार

नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी (सीबीआई) ने बच्चों से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में तमिलनाडु के तंजावुर से एक 35 वर्षीय पीएचडी छात्र को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने कथित रूप से इलेक्ट्रॉनिक तौर पर बाल यौन शोषण सामग्री तैयार करने और प्रसारित करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने दो नाबालिगों (एक लड़का और एक लड़की) को यौन कार्यके लिए मजबूर किया था।

उन्होंने कहा कि सीबीआई को इंटरपोल डेटाबेस से बाल यौन शोषण की तस्वीरें और वीडियो मिले थे। डिजिटल फोरेंसिक उपकरणों का उपयोग करके विश्लेषण करने पर पता चला कि यह घटना तंजावुर जिले की है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने आरोपी के कई परिसर में तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए। आरोपी पर आरोप था कि वह पिछले चार साल से एक बच्चे का यौन शोषण कर रहा था, जिसके नग्न वीडियो और तस्वीरें उसके गूगल अकाउंट पर अपलोड की गई थीं। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने दो नाबालिगों (एक लड़का और एक लड़की) को यौन कार्यके लिए मजबूर किया था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी ने उनकी तस्वीरें खींचने के साथ वीडियो बना लिया और इन्हें इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी देकर उन्हें और लड़कियों को लाने के लिए मजबूर किया।

चुनाव की मांग करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, जनता का सामना करने से से डर रही बीजेपी

नईदिल्ली। विपक्षी दलों की ओर से जम्मू-कश्मीर में लगातार चुनाव कराने की मांग की जा रही है। विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग (ईसी) से मुलाकात भी कर चुका है। इन सब के बीच चुनाव की मांग पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर इसको लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी डरी हुई है तो चुनाव नहीं होंगे और अगर वे लोगों का सामना करने के लिए तैयार हैं तो चुनाव कराने की संभावनाएं हैं। केंद्र ने 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इसके बाद से अब तक बहां चुनाव नहीं हुए है। निर्वाचन आयोग (ईसी) से मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि सीईसी ने हमारी बात सुनी और आश्वासन दिया कि आयोग जल्द ही इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करेगा।"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023